@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive www.kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया कमल संदेश विशेषांक 'नए भारत के प्रणेता' का विमोचन

वर्ष-15, अंक-19 01-15 अक्टूबर, 2020 (पाक्षिक) ₹20

कृषि क्षेत्र में क्रांति

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायाकल्प

पटना (बिहार) में भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, बिहार के उप–मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा बिहार प्रदेश चुनाव प्रभारी श्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) के उपलक्ष्य में छपरौली गांव (गौतमबुद्ध नगर, उप्र) से 'सेवा सप्ताह' अभियान का शुभारंभ करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में 'कमल संदेश' विशेषांक 'नए भारत के प्रणेता' का विमोचन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा जिला कार्यालय सोनीपत (हरियाणा) में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) के उपलक्ष्य में 'सेवा सप्ताह' कार्यक्रम के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **व्यापक सुधारों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र पर 'भरोसे की कमी का संकट' मंडरा रहा: नरेन्द्र मोदी**

संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुलाई गई महासभा की बैठक में 22 सितम्बर को अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि व्यापक सुधारों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र पर...

श्रद्धांजलि

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी नहीं रहे 13

लेख

मोदी हैं, तो भरोसा है 16

किसान कल्याण के नए मापदंड 19

नरेन्द्र मोदी: 'एक भारत—श्रेष्ठ भारत' के शिल्पकार 20

नरेन्द्र मोदी: विकसित भारत का वैश्विक चेहरा 22

नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व मानवता के कल्याण के लिए 24

अन्य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 'सेवा सप्ताह' कार्यक्रम 08

संसद में पारित हुआ युगांतकारी कृषि विधेयक 10

मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों ने 27 विधेयक किए पारित 12

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार प्रवास 26

प्रधानमंत्री ने बिहार में 14,258 करोड़ रुपये की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला 27

पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती (25 सितंबर) पर कार्यक्रम 28

07 **समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा मोदीजी के जीवन का ध्येय**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 14 सितंबर 2020 को गौतम बुद्ध...

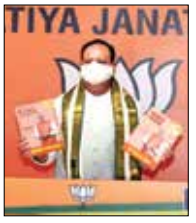

14 **प्रधानमंत्रीजी ने राजनीतिक कार्य-संस्कृति को बदल कर रख दिया है**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 18 सितंबर, 2020 को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी...

26 **संपूर्णता के साथ किसान का विकास होना चाहिए: जगत प्रकाश नड्डा**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 12 सितंबर 2020 को बिहार के मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा में...

30 **राज्य कोविड की टेस्टिंग, ट्रेसिंग पर प्रभावी उपाय करते रहेंगे: प्रधानमंत्री**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितंबर को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

नरेन्द्र मोदी

हमारा वैचारिक तंत्र और राजनीतिक मंत्र साफ है, गोलमोल नहीं है। हमने इसे जी कर दिखाया है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। नेशन फर्स्ट- यही हमारा मंत्र है, यही हमारा कर्म है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को 21वीं सदी की राजनीति में अपनी यह पहचान और सशक्त करनी है।

अमित शाह

जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा (संशोधन) विधेयक का लोक सभा में पारित होना जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस ऐतिहासिक बिल से जम्मू-कश्मीर के लोगों का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना सच हो गया है! कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी अब जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होगी।

बी. एल. संतोष

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग समितियों का गठन किया गया। एक बेहतर भारत के लिए सुधारों की शुरुआत करनेवाले सभी मोर्चों पर नरेन्द्र मोदी सरकार त्वरित गति से आगे बढ़ रही है। बेंगलुरु के डॉ. एम.के. रमेश और डॉ. बी.एन. गंगाधर क्रमशः पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन और नैतिकता समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सभी सदस्यों को बधाई।

facebook

लंबे समय से हम ये कहते आए थे कि शिक्षा नीति भारत का प्रतिबिंब होना चाहिए। नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वैचारिक पृष्ठभूमि पर जितने लोग हैं, सबने इसे सराहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया और फिर शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ।

— जगत प्रकाश नड्डा

बिहार राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूती देते हुए 14,258 करोड़ रुपये की कुल लागत और 350 कि.मी. कुल लंबाई की 9 सड़क परियोजनाओं का 21 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया गया। ये सड़क परियोजनाएं बिहार में तेज विकास और बेहतर संपर्क प्रस्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगी। इससे यातायात एवं वस्तुओं की आवाजाही सुगम होगी और बिहार सहित पड़ोसी राज्यों की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।

— नितिन गडकरी

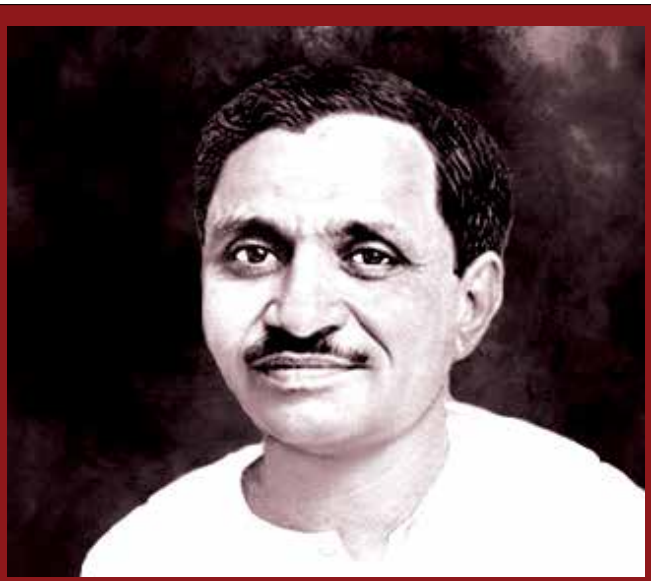

कमल संदेश परिवार की ओर से
एकात्म मानववाद के प्रणेता
पं. दीनदयाल उपाध्याय
जयन्ती (25 सितम्बर) पर उन्हें
शत-शत नमन!

कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव

हाल ही में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र को कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किए गए सुधारों के लिए इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण दो विधेयकों को पारित कर किसानों की आय को दुगुना करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है, अब किसान अपनी उपज को किसी को भी और किसी भी स्थान पर बेचने को स्वतंत्र हैं। इससे किसानों की अपनी उपज के मोल-भाव करने की शक्ति बढ़ी है और उसे अच्छे मूल्य प्राप्त होंगे। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर विधेयक, 2020- ऐसे दो विधेयक हैं जिससे अब किसान देश के किसी भी भाग में अपनी उपज बेच सकेगा तथा किसी भी कृषि व्यापार इकाई से अनुबंध कर सकेगा। इससे जहां एक ओर किसानों के उपज की कुशल, पारदर्शी एवं बाधा-रहित अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इससे किसानों को अपनी उपज का अधिकतम मूल्य मिलने के साथ कृषि क्षेत्र में आधुनिक संरचना का विकास होगा।

किसानों के कल्याण के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए संसद ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित कर अनाज, दालें, तेलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू की आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया। इससे न केवल कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश के दरवाजे खुल गए, बल्कि किसानों को उनकी उपज का अधिकतम दाम भी मिल पाएगा जो बंपर पैदावार की स्थिति में नहीं मिल पाता था। इस संशोधन से कृषि क्षेत्र उन जंजीरों से आजाद हो गया, जिसने इसके विकास को जकड़ रखा था। अब इस क्षेत्र में भी अवसंरचनाओं का विकास और आधुनिकीकरण होगा और हमारे किसान पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे।

शुरू से ही मोदी सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे देश में किसानों की आय दुगुनी होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि अब तक उपेक्षित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक बजटीय आवंटन मिले तथा साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार कर विश्वस्तरीय स्पर्धा में इसकी सकारात्मक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है।

जब भी देश के सामने कोई चुनौती आई, देश के अन्नदाताओं ने आगे बढ़कर देश की झोली भर दी। आज जब देश कोविड-19 महामारी से पूरी शक्ति से लड़ रहा है, भारत के किसानों ने यह प्रमाणित कर दिया कि वे चुनौतियों से दो-दो हाथ करने में और भी अधिक शक्ति से कार्य कर सकते हैं। एक ओर जहां पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद की बिक्री अधिक हुई, वहीं इस वर्ष खरीफ फसलों की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में 8.56 प्रतिशत अधिक रही। अब तक सामान्य वर्षा रहने के कारण यह अनुमान है कुल उपज पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहने वाली है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि एक ओर तो किसान हर संकट में अपना अधिकतम योगदान करते हैं, परंतु कांग्रेस ने दशकों तक किसानों की कोई सुध नहीं ली। यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं करिश्माई नेतृत्व में ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन होगा तथा देश के किसान समृद्ध एवं सशक्त होंगे।

शुरू से ही मोदी सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे देश में किसानों की आय दुगुनी होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि अब तक उपेक्षित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक बजटीय आवंटन मिले तथा साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार कर विश्वस्तरीय स्पर्धा में इसकी सकारात्मक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। जिस प्रकार से कृषक, कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पिछले छह वर्षों में प्राथमिकता दी गई है, इसके पूर्व में कभी नहीं हुआ। एक लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ई-गोपाला, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, उपज का डेढ़ गुणा करने जैसे अनेक कदमों से किसानों को उपज का दुगुना मूल्य दिलाने के लिए मोदी सरकार कृतसंकल्पित है। हमारे देश के किसान न तो कमजोर हैं न ही उपज कम है और न ही मेहनत में कमी है। कमी थी तो सरकार की सोच, मानसिकता एवं व्यवस्था में सुधार के लिए दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति की। अब जबकि मोदी सरकार मजबूती से किसानों के हित में बड़े-बड़े निर्णय ले रही है उससे न केवल किसान आत्मनिर्भर होंगे, बल्कि देश 'आत्मनिर्भर' बनेगा। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

व्यापक सुधारों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र पर 'भरोसे की कमी का संकट' मंडरा रहा: नरेन्द्र मोदी

संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुलाई गई महासभा की बैठक में 22 सितम्बर को अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि व्यापक सुधारों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र पर 'भरोसे की कमी का संकट' मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पुराने ढांचे के साथ आज की चुनौतियों से नहीं निपट सकते। संयुक्त राष्ट्र व्यापक सुधार के बिना विश्वास संबंधी संकट से जूझ रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि आज की परस्पर संबद्ध दुनिया के लिए हमें एक ऐसे बहुपक्षीय सुधार की आवश्यकता है; जो आज की वास्तविकताओं को दर्शाता हो, सभी हितधारकों को आवाज देता हो, समकालीन चुनौतियों को दूर करता हो और मानव कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता हो। भारत इस दिशा में अन्य सभी देशों के साथ काम करने के लिए तत्पर है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के कारण आज हमारी दुनिया बेहतर जगह बन पाई है। हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के ध्वज तले शांति और विकास के कार्यों को बेहतर किया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन भी शामिल है जहां भारत का अग्रणी योगदान रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि, हमने काफी कुछ हासिल किया है लेकिन मूल मिशन अब भी अधूरा रह गया है। हम आज जिस दूरगामी घोषणा पत्र को अपना रहे हैं उससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों में अभी भी काफी काम करने की जरूरत है; संघर्ष को रोकने में, विकास सुनिश्चित करने में, जलवायु परिवर्तन को रोकने में, असमानताओं को कम करने में और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में। इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है।

उन्होंने कहा कि पचहत्तर वर्ष पहले युद्ध की विभीषिका से एक नई उम्मीद पैदा हुई। मानव इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया के लिए एक संस्था बनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के एक संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत उस महान दृष्टिकोण का हिस्सा था। इसने भारत के अपने दर्शन 'वसुधैव कुटुम्बकम' को प्रतिबिंबित किया जो पूरी सृष्टि को एक परिवार के रूप में देखता है।

संयुक्त राष्ट्र के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर 193-सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अग्रगामी राजनीतिक संकल्प को अपनाया, जिसमें आतंकवाद से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने, बहुपक्षवाद में सुधार करने, समावेशी विकास और कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने की बेहतर तैयारी का आह्वान किया गया। ■

गौतम बुद्ध नगर (उप्र) में 'सेवा सप्ताह' कार्यक्रम

समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा मोदीजी के जीवन का ध्येय: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी विगत छह वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष 14 से 20 सितंबर तक 'सेवा सप्ताह' आयोजित करती रही है। कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर सफाई कार्यक्रम, पौधरोपण, श्रमदान, रक्तदान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 14 सितंबर 2020 को गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के ग्राम छपरौल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस (17 सितंबर) के शुभ अवसर पर 'सेवा सप्ताह' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

देशव्यापी 'सेवा सप्ताह' कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के ग्राम छपरौली के पार्क में वृक्षारोपण किया और यहीं पर सेवा बस्ती में फलों का वितरण किया। इसके पश्चात् उन्होंने ग्रामवासियों से संवाद किया। इस अवसर पर श्री नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल, प्रदेश महामंत्री श्री अश्विनी त्यागी, लोक सभा सांसद डॉ. महेश शर्मा, राज्य सभा सांसद श्री सुरेंद्र नागर सहित क्षेत्र के सभी विधायक एवं बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस वर्ष 17 सितंबर को अपने जीवन के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं, इसलिए इस बार के 'सेवा सप्ताह' कार्यक्रम की थीम भी '70' रखी गई है। इस 'सेवा सप्ताह' कार्यक्रम के दौरान 14 से 20 सितंबर तक हर जिले में 70 स्थानों पर सेवा भाव के साथ स्वच्छता कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन, दिव्यांगों को उपकरणों का वितरण, अस्पतालों एवं गरीब बस्तियों में फलों का वितरण और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके साथ ही हर जिले में पार्टी कार्यकर्ता कम से कम 70 लोगों को 'सेवा सप्ताह' कार्यक्रम से 'सेवाव्रती' के रूप में जोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त हर जिले में 70 वर्चुअल रैलियां भी आयोजित की जायेगी।

श्री नड्डा ने कहा कि सेवा ही हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री एवं विश्व की महान शख्सियत श्री नरेन्द्र मोदी का प्रमुख लक्ष्य रहा है। समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा ही उनके जीवन का ध्येय रहा है और यह भाव उनमें बचपन से रहा है। उनके बाल्य जीवन पर बनी फिल्म 'चलो जीते हैं' का जिक्र करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए इसका मतलब है चलो, दूसरों के लिए जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बचपन की एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह बालक नरेन्द्र ने अपनी प्राइज मनी से अपने साथी के लिए स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराने में मदद की थी। 10-12 साल की उम्र से ही दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्तित्व श्री नरेन्द्र मोदी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था।

श्री नड्डा ने कहा कि पहले राजनीति में शुरू में 'सेवा' के बदले 'मेवा' खाने का काम होता था। आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीबों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों और वंचितों को मुख्यधारा में लाने का काम हो रहा है। 2014 में आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांव और ढाई करोड़ से अधिक घर बिजली से वंचित थे और अंधेरे में जीने को विवश थे। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं जिन्होंने न केवल हर गांव और हर घर में बिजली पहुंचाई बल्कि 8 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया, 32 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खुलवाये और किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सहायता राशि भी पहुंचाई। लॉकडाउन के समय तीन महीने तक मोदी सरकार ने गरीब महिलाओं को तीन मुफ्त गैस सिलिंडर उपलब्ध करवाई। साथ ही, देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मार्च से नवंबर तक मुफ्त राशन का भी प्रबंध किया। लॉकडाउन के तीन महीनों में 20 करोड़ महिला जन-धन खाता धारकों के एकाउंट में 1500 रुपये (500-500 रुपये की तीन किस्तें) पहुंचाई गई। ■

'हमने कभी भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 सितंबर 2020 को चांदनी चौक, दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 'सेवा सप्ताह' के तहत कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने वृक्षारोपण किया, एवं लाभार्थियों को पल्स ऑक्सीमीटर, दिव्यांगों को ट्राई साइकिल, कान की मशीन और हाथ-ठेला (रेहड़ी) इत्यादि का वितरण किया। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित विशाल जन-समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के विकास हेतु कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी और विशाल संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा ने संघर्षों के कई पड़ाव को पार करते हुए यहां तक का सफ़र तय किया है। हमने कई उतार-चढ़ाव देखे लेकिन हमने कभी भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज समग्र राष्ट्र में राजनीति की कार्य संस्कृति में व्यापक बदलाव हुआ है और विकास आधारित राजनीति के नए युग का शुभारंभ हुआ है। जब प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधान सेवक कहें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हम सत्ता के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने और उनके उत्थान के लिए राजनीति में आये हैं।

श्री नड्डा ने 2014 से पहले की देश की धूमिल छवि को रेखांकित करते हुए कहा कि 2014 से पहले के कांग्रेस शासन में देश भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था, कोई भी देश में निवेश करने को तैयार नहीं था लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की उस छवि को बदल कर इसे विश्व के निर्णायक राष्ट्र के तौर पर प्रतिष्ठित किया। अपने कृतित्व से श्री मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रतिष्ठित हुए। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यह कहने को विवश हो जाएं कि वह दिन दूर नहीं जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल का होगा तब हमें यह अनुभूति होती है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में देश की छवि किस तरह बदल रही है। जब हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम से अमेरिका के राष्ट्रपति अचंभित होकर हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए जनता के प्यार और समर्थन को देखकर अचंभित रह जाय तब समझ में आता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया का भारत को देखने के नजरिये में किस तरह बदलाव आया है। दुनिया के सात देश जब अपने सर्वोच्च सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सम्मानित करते हों, तब मालूम पड़ता है कि भारत की वैश्विक छवि में किस तरह बदलाव हो रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सेवा ही संगठन' के एक आह्वान पर अपने आपको मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया, वह अपने आप में अलौकिक और अद्भुत है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के दौरान 25 करोड़ से अधिक फूड पैकेट्स, 5 करोड़ से अधिक राशन किट्स और साढ़े पांच करोड़ से अधिक फेस कवर का वितरण किया। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने भी इस दौरान सेवा कार्य का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक करोड़ फूड पैकेट्स, लाखों राशन किट्स, 90 लाख फेस कवर और 10 लाख 'काढ़ा किट्स' का भी वितरण किया। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए भोजन और बुजुर्गों के लिए दवाइयों की भी व्यवस्था की। मैं मानवता के इस यज्ञ में पार्टी कार्यकर्ताओं के योगदान को नमन करता हूं। ■

प्रधानमंत्रीजी की जीवनी से संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 15 सितंबर 2020 को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस (17 सितंबर) के अवसर पर प्रधानमंत्री जी की जीवनी से संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष 14 से 20 सितंबर तक 'सेवा सप्ताह' मनाती है। इस अवसर पर वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन और स्वच्छता अभियान जैसे कई सेवा कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रदर्शन का उद्घाटन करते समय श्री नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश जावडेकर, पार्टी उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह, कार्यालय प्रभारी श्री महेंद्र पांडेय एवं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सरदार आर. पी. सिंह सहित कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। ■

'मोदीजी ने पार्टी को 'सेवा ही संगठन' के रूप में आगे बढ़ाया है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 सितंबर, 2020 को जिला भाजपा कार्यालय, सोनीपत (हरियाणा) में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 'सेवा सप्ताह' के तहत आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया और इस अवसर पर स्थानीय जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के विशाल जन-समुदाय को संबोधित किया। 'सेवा सप्ताह' कार्यक्रम के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला भाजपा कार्यालय में पौधारोपण किया। इसके पश्चात् उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में ही उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन से संबंधित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अपने उद्बोधन के पश्चात् श्री नड्डा जी ने लाभार्थियों को चश्में का वितरण किया और ब्लड डोनेशन कैंप का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनिल जैन, सोनीपत से लोक सभा सांसद श्री रमेश चंद्र कौशिक, सांसद श्री संजय भाटिया, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री सुनील देवधर एवं पार्टी के कई विधायक एवं बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्य किसी उद्देश्य को लेकर होता है और वह उद्देश्य सदैव ही समाज सेवा के प्रति समर्पित होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी को 'सेवा ही संगठन' के रूप में आगे बढ़ाया है। उनके विचारों एवं उनके द्वारा दिखाए गए सेवा मूल्यों के रास्ते पर पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ें, यही उनके जन्म दिवस पर आयोजित देशव्यापी कार्यक्रम 'सेवा सप्ताह' का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि उनका सामाजिक पक्ष बहुत बड़ा और व्यापक है। वे बाल्यकाल से ही दूसरों के लिए जीते आ रहे हैं। ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं जब उन्होंने स्वयं के बजाय समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचा और उसे जिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने जीवन को इस तरह जिया जिससे कि देश के गरीबों, दलितों, किसानों, शोषितों और वंचितों को ताकत मिल सके और वे विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। आर्थिक मदद देने के साथ-साथ उन्होंने किसानों, गरीबों, दलितों व पिछड़ों का सामाजिक सशक्तिकरण भी किया और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया।

सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आजादी के 70 सालों तक देश के हजारों गांव और करोड़ों घर बिजली से अछूते थे, करोड़ों महिलाओं के पास गैस कनेक्शन नहीं था, स्वास्थ्य के खर्चे के बोझ से गरीब वर्ग पीड़ित था, करोड़ों गरीबों के पास अपना छत नहीं था, शुद्ध पीने का पानी नहीं था और यहां तक कि करोड़ों लोगों के पास बैंक एकाउंट तक नहीं था। आखिर किसलिए श्री नरेन्द्र मोदी का इंतजार था? प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलते हुए इसे विकास आधारित राजनीति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने जनता को सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगना सिखाया। विगत छः वर्षों में लगभग 34 करोड़ लोगों के जन-धन एकाउंट खोले गए, 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया, 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया, 8 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई, ढाई करोड़ से अधिक घरों और 18 हजार से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाई गई और डेढ़ करोड़ से अधिक गरीब को घर दिया गया। हर घर में शुद्ध पीने का पानी, बिजली, गैस कनेक्शन और शौचालय की सुविधा दी जा रही है। ■

'लॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड' वी पुस्तक का विमोचन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 सितंबर 2020 को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से डॉ. हरीश बरनवाल द्वारा रचित 'लॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड' वी पुस्तक (vBook) का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन विमोचन किया। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय, पुस्तक के लेखक डॉ. हरीश बरनवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी एवं श्री डॉ. रमेश चन्द्र गौड़ भी वर्चुअली उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्रुति नागपाल जी ने किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि 'लॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड' वी पुस्तक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से संबंधित 251 रिकॉर्ड्स सम्मिलित किए गए हैं, जो प्रधानमंत्री जी के विराट व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। ■

संसद में पारित हुआ युगांतकारी कृषि विधेयक

संसद ने कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 20 सितंबर को दो विधेयक पारित कर दिए। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 को लोकसभा ने 17 सितंबर, 2020 को पारित कर दिया था जबकि राज्य सभा ने 20 सितंबर को इस विधेयक को पारित कर दिया।

यह विधेयक 5 जून, 2020 को आए अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर, 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया।

विधेयक के संबंध में बोलते हुए श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को उनके उत्पाद की बेहतर कीमत दिलाने और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए पिछले 6 वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं।

कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020

मुख्य प्रावधान

- किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें।
- यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा।
- किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा।
- विधेयक किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके।
- मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फॉर्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी।
- किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाए किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके।

शंकाएं

- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की ख़रीद बंद हो जाएगी।
- कृषक कृषि उत्पाद यदि पंजीकृत बाजार समितियों (एपीएमसी मंडियों) के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी।
- ई-नाम जैसे सरकारी ई-ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा?

समाधान

- एमसपी पर पहले की तरह खरीद जारी रहेगी। किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे। आगामी रबी सीजन के लिए एमएसपी बढ़ी हुई दर से घोषित की गई है।
- मंडिया समाप्त नहीं होंगी, वहां पूर्ववत व्यापार होता रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा।

'आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक' को संसद की मंजूरी

संसद ने अनाज, तिलहनों, खाद्य तेलों, प्याज एवं आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को 22 सितंबर को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने इससे संबंधित 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक' को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा।

इस संदर्भ में केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि उत्पादन, उत्पादों को जमा करने, आवागमन, वितरण एवं आपूर्ति की स्वतंत्रता से बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा तथा कृषि क्षेत्र में निजी एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा।

विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री रावसाहेब दानवे ने कहा कि कानून के जरिये स्टॉक की सीमा थोपने से कृषि क्षेत्र में निवेश में अड़चनें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि साढ़े छह दशक पुराने इस कानून में स्टॉक रखने की सीमा राष्ट्रीय आपदा तथा सूखे की स्थिति में मूल्यों में भारी वृद्धि जैसे आपात हालात उत्पन्न होने पर ही लागू की जाएगी।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक' राज्य सभा में पारित होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण, मूल्य स्थिरता लाने में सहायक 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक' के राज्यसभा में पारित होने पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं व सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं। ■

- मंडियों में ई-नाम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा। इससे पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी।

कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020

मुख्य प्रावधान

- कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ना। कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान को उसकी उपज के दाम निर्धारित करना। बुवाई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन। दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ।
- इस विधेयक की मदद से बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से हटकर प्रायोजकों पर चला जाएगा। मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा।
- इससे किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक होगी।
- इससे विपणन की लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी।
- किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिवस में स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है।
- कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को बढ़ावा देना।

शंकाएं

- अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और वे कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे।
- छोटे किसान संविदा खेती (कांट्रेक्ट फार्मिंग) कैसे कर पाएंगे? क्योंकि प्रायोजक उनसे परहेज कर सकते हैं।
- नई व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी होगी।
- विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को लाभ होगा।

स्पष्टीकरण

- किसान को अनुंबध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकेगा। उन्हें अधिक से अधिक 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा।
- देश में 10 हजार कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं। यह समूह (एफपीओ) छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे।
- अनुबंध के बाद किसान को व्यापारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। खरीदार उपभोक्ता उसके खेत से ही उपज लेकर जा सकेगा।
- विवाद की स्थिति में कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने की आवश्यक्ता नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही विवाद के निपटाने की व्यवस्था रहेगी। ■

प्रधानमंत्री ने संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने पर किसानों को दी बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने को भारतीय कृषि के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए किसानों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट कर 20 सितंबर को कहा कि भारतीय कृषि के इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने पर हमारे मेहनती किसानों को बधाई! इससे न केवल कृषि क्षेत्र का कायाकल्प होगा, बल्कि करोड़ों किसानों का सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।

श्री मोदी ने कहा कि दशकों से भारतीय किसान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए विवश रहे और बिचौलियों के हाथों परेशान होते रहे। संसद द्वारा पारित विधेयक किसानों को ऐसी विपत्तियों से मुक्त कराएंगे। ये विधेयक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों में तेजी लाएंगे और उनके लिए अधिक समृद्धि सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर से कह रहा हूं, 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (एमएसपी) की व्यवस्था रहेगी। सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम उनकी मदद करने और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 20 सितंबर को संसद में कृषि विधेयकों के पारित होने पर कहा कि देश का किसान अब अपनी मर्जी का मालिक होगा। श्री नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि कृषि एवं किसानों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों के संसद में पास होने पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करता हूं और देश के सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं समर्थन के लिए सभी सांसदों एवं राजनीतिक दलों को भी साधुवाद देता हूं।

उन्होंने कहा कि अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसानों को उपज बेचने का विकल्प देकर उन्हें सशक्त बनाया गया है। बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का भी लाभ किसान ले सकेंगे। इससे जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान किसान के घर पर ही उपलब्ध होगा। ■

मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों ने 27 विधेयक किए पारित

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने मानसून सत्र 2020 को लेकर 24 सितंबर को बताया कि मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में लगभग 167 प्रतिशत और राज्यसभा में लगभग 100.47 प्रतिशत कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 22 विधेयक (16 लोक सभा में और 6 राज्य सभा में) पेश किए गए।

श्री जोशी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा 27 विधेयक पारित किए गए, जो विधेयकों के पारण की अभी तक की सर्वोत्तम दर अर्थात 2.7 विधेयक प्रतिदिन है। 11 अध्यादेशों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अंतःसत्रावधि के दौरान प्रख्यापित किए गए सभी 11 अध्यादेशों को मानसून सत्र के दौरान संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

श्री जोशी ने कहा कि 14 सितंबर को शुरू हुए संसद का मानसून सत्र का समापन 1 अक्टूबर को होना था, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में आवश्यक कामकाज के बाद कोविड-19 महामारी के जोखिम के कारण सदन की कार्यवाही 23 सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान 10 दिनों में कुल 10 बैठकें हुईं।

लोक सभा ने तीन ऐतिहासिक श्रम संहिताओं को किया पारित

लोक सभा ने 22 सितंबर को तीन ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली श्रम संहिताओं को पारित कर दिया है। ये संहिताएं हैं- (i) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (ii) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 तथा (iii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020।

नई श्रम संहिताओं में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्व-नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है। ईएसआईसी और ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा आवरण को और व्यापक बनाकर सभी कामगारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

इससे गिग तथा प्लेटफार्म कामगारों के साथ-साथ 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 'सामाजिक सुरक्षा निधि' की स्थापना से सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज को और व्यापक बनाने में सहायता मिलेगी। नियतकालिक कर्मचारी की सेवा शर्तें, उपदान, अवकाश और सामाजिक सुरक्षा नियमित कर्मचारी की तरह ही होंगी।

महिला कामगारों को पुरुष कामगारों की तुलना में वेतन की समानता और दुर्घटना की स्थिति में जुर्माने का 50 प्रतिशत भाग कामगार को अन्य बकायों के साथ दिया जाएगा। प्रवासी कामगारों को वर्ष में एक बार अपने गृह नगर की यात्रा के लिए नियोक्ता से यात्रा भत्ता प्राप्त होगा।

राज्यसभा से पास हुआ विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020

राज्यसभा ने 23 सितंबर को विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी, जिसमें विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं।

विधेयक के उद्देश्यों के अनुसार एफसीआरए के तहत पूर्व अनुमति या पंजीकरण अथवा एफसीआरए के लाइसेंस नवीनीकरण का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब अपने सभी पदाधिकारियों या निदेशकों के आधार नंबर देने होंगे, विदेशी नागरिक होने की स्थिति में पासपोर्ट की एक प्रति या ओसीआई कार्ड की प्रति देना जरूरी होगा।

विधेयक के प्रावधानों से विदेशों से आने वाले अभिदाय की निगरानी में आसानी होगी और पैसे के दुरुपयोग पर रोक लग सकेगी। एनजीओ को जिस कार्य के लिये पैसा मिले, वह उसी कार्य में खर्च होना चाहिए। एनजीओ को विदेशी अनुदान के संबंध में दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में खाता खोलना होगा।

हालांकि, इसके लिए उन्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं होगी और अपने आसपास की किसी भी शाखा के जरिए यह खाता खोला जा सकता है। इस संशोधन विधेयक में एनजीओ के प्रशासनिक खर्च को मौजूदा 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। ■

रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भारी वृद्धि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 21 सितंबर को फसल वर्ष 2020-21 (जुलाई-जून) के रबी सीजन की छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। दलहन फसलों में चना का मूल्य 225 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5100 रुपये कर दिया गया है। मसूर के एमएसपी में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है जो 4800 रुपये से बढ़कर 5100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

रबी सीजन की प्रमुख फसल सरसों का एमएसपी 4425 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4650 रुपये कर दिया गया है। कुसुम का भाव 5215 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5327 रुपये किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को लागत मूल्य पर 106 प्रतिशत तक लाभ मिलेगा। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि गेहूं के मूल्य में जहां 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। वहीं जौ का मूल्य 1525 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ■

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी नहीं रहे

(1 जून, 1955 - 23 सितंबर, 2020)

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी का 23 सितंबर को एम्स में निधन हो गया। वे 65 साल के थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री अंगड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि श्री अंगड़ी के निधन से राष्ट्र ने एक प्रख्यात नेता, एक शिक्षाविद, एक प्रतिष्ठित सांसद और एक सक्षम प्रशासक खो दिया है। शोक प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार और सम्पूर्ण राष्ट्र की ओर से मंत्रिमंडल शोक संतप्त परिवार के प्रति हृदय से शोक संवेदना व्यक्त करता है।

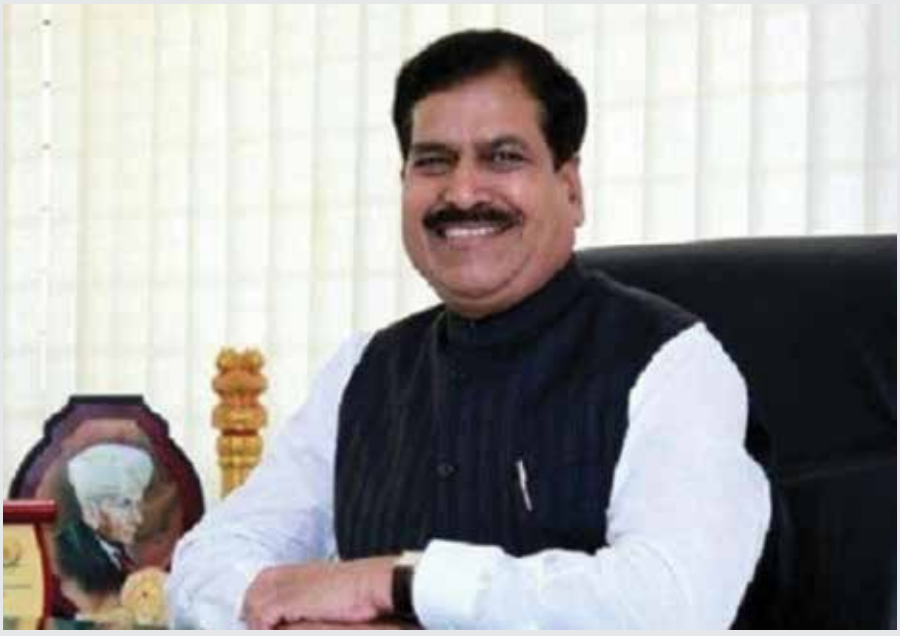

जीवन परिचय

1 जून, 1955 को कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के केके कोप्पाक गांव में जन्मे श्री अंगड़ी ने एसएसएस समिति कॉलेज, बेलगावी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद राजा लखमगौड़ा लॉ कॉलेज, बेलगावी से कानून की डिग्री प्राप्त की।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में वे 1996 में पार्टी की बेलगावी जिला इकाई के उपाध्यक्ष बने। 2001 में उन्होंने बेलगावी जिला इकाई के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया और 2004 में बेलगावी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने तक वह इस पद पर बने रहे। वह मतों के बड़े अंतर से जीतकर 14वीं लोकसभा के सदस्य बने। वह 2009, 2014 और 2019 में बेलगावी से लोकसभा के लिए पुनःनिर्वाचित हुए।

उन्होंने ने खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण; मानव संसाधन विकास; और रक्षा की स्थायी समितियों के सदस्य के रूप में तथा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने संसद सदस्यों के पेंशन, वेतन और भत्तों की संयुक्ति समिति; केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति, सदन समिति और याचिका समिति के सदस्यों के रूप में भी कार्य किया। श्री अंगड़ी मई, 2019 में केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री बने।

उनकी उद्योग, कृषि और गरीबों के लिए शिक्षा में विशेष रुचि थी और वह अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल रहे। वर्ष 2009 से वह सुरेश अंगड़ी एजुकेशन फाउंडेशन, बेलगाम के अध्यक्ष थे। उन्हें पढ़ने और भ्रमण का शौक था। ■

शोक संदेश

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी के निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि श्री सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि वे एक समर्पित सांसद और प्रभावी मंत्री थे जिनका हर कोई मुरीद था। उनका निधन पीड़ा देने वाला है। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवदेनाएं उनके परिजनों और उनके चाहने वालों के साथ हैं। ॐ शांति।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी जी के निधन से अत्यंत दुःख हुआ। वह एक उल्लेखनीय नेता थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन संगठन के लिए समर्पित कर दिया और अत्यंत परिश्रम और करुणा के साथ समाज की सेवा की। उनके परिवार तथा अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदना व प्रार्थना है।

'कमल संदेश' विशेषांक 'नए भारत के प्रणेता' का विमोचन

प्रधानमंत्रीजी ने राजनीतिक कार्य-संस्कृति को बदल कर रख दिया है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 18 सितंबर, 2020 को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस (17 सितंबर) के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'कमल संदेश' द्वारा प्रकाशित विशेषांक 'नए भारत के प्रणेता' का विमोचन किया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनिल जैन, भाजपा पत्रिका एवं प्रकाशन विभाग के संयोजक एवं 'कमल संदेश' के कार्यकारी संपादक डॉ. शिवशक्ति बक्सी, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के सचिव श्री नंद किशोर गर्ग, कोषाध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल और राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख डॉ. संजय मयूख भी उपस्थित थे।

कमल संदेश के इस विशेषांक 'नए भारत के प्रणेता' में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व, कृतित्व और विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस विशेषांक में प्रधानमंत्री जी का जीवन परिचय, बाल्यकाल से लेकर अब तक के उनके जीवन की चित्रमयी यात्रा, उनके चुने हुए उद्बोधन, उनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख कविताओं को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के 70 ऐतिहासिक निर्णयों को भी स्थान दिया गया है। साथ ही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रचित पुस्तकों पर भी चर्चा इस विशेषांक में की गई है।

विशेषांक का विमोचन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस (17 सितंबर) के अवसर पर 14 से 20 सितंबर तक 'सेवा सप्ताह' मना रही है। इस अवसर पर डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास की ओर से इस विशेषांक का विमोचन करना एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए न्यास के सभी पदाधिकारियों एवं संपादक मंडल के सदस्यों को साधुवाद देता हूं।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करता यह विशेषांक भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए काफी प्रेरणादायक है। इसमें उनकी पूरी जीवन यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। यह संजोने वाला अंक है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने कई सरकारें देखी हैं लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण और आर्थिक सुधारों से लेकर देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने हेतु लाये गए बदलावों जो देश और दुनिया ने जो देखा है, वह अकल्पनीय और अद्भुत है। प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक कार्य-संस्कृति को बदल कर रख दिया है। 2014 से पहले कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकारों के दौरान चुनाव में विकास का रिपोर्ट कार्ड रखने की जगह जाति आधारित वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति की जाती थी। पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीति में विकास, सेवा, जन-कल्याण और जनता के लिए समर्पण की संस्कृति का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जी ने लोक लुभावने वादे और नारे के बजाय जनता की भलाई और गरीबों के उत्थान के दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाते हुए गरीब कल्याण को सही अर्थों में चरितार्थ कर दिखाया जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति आज विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हर योजनाओं

में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति स्पष्टतः दिखाई देती है चाहे वह हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने की योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, स्टार्ट-अप व स्टैंड-अप योजना हो, कृषि सम्मान निधि हो, जन-धन योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना। उन्होंने कहा कि कल ही कृषि से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 लोक सभा में पारित हुए हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट वाला विधेयक दो दिन पहले ही पारित हुआ है। कृषि से जुड़े ये तीनों विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा और किसान सशक्त होंगे।

कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में यह वादा किया था कि किसानों को एपीएमसी से बाहर निकाल कर लायेंगे और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को बदलेंगे। जो लोग इन कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में किसान और उनके उत्पाद की बिक्री के बीच में मौजूद बिचौलियों की भाषा बोल रहे हैं। श्री नड्डा ने जोर देते हुए कहा कि एमएसपी अर्थात् न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं सरकारी खरीद अर्थात् एपीएमसी की व्यवस्था बनी रहेगी। विधेयक किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। इसके तहत एक परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है जिसमें किसान कानूनी बंधनों से आजाद होंगे। किसानों के पास मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की विवशता नहीं होगी। अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसानों को उपज बेचने का विकल्प देकर उन्हें सशक्त बनाया गया है। इस विधेयक के अनुसार जरूरी नहीं कि किसान राज्य की सीमाओं में रहकर ही फसलों की बिक्री करें। साथ ही बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का भी लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझ कर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ताकि किसान लाभ न उठा सकें।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहले भी कहा है कि हमें दबाव की राजनीति में नहीं आना है और हमारी सरकार वह काम करती रहेगी जो देश के गांव, गरीब और किसान के लिए जरूरी हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में आज बदली हुई तस्वीर दिख रही है। उन्होंने याद दिलाया कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करते समय भी इस योजना का जम कर विरोध किया गया था, लेकिन आज वही आयुष्मान भारत योजना देश के गरीबों के लिए सबसे बड़ी वरदान साबित हो रही है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संगठन को राजनीति के साथ-साथ सेवा कार्य का एक माध्यम भी बनाया है। उनके 'सेवा ही संगठन' के आह्वान पर पूरी भारतीय जनता पार्टी मानवता की सेवा में अनवरत और अविरल भाव से लॉकडाउन के समय लगी रही, जबकि बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां लॉकडाउन की स्थिति में थी। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के समय देश भर में 25 करोड़ फ़ूड पैकेट्स, 5 करोड़ राशन किट्स और 1 करोड़ से अधिक फेसकवर का वितरण किया। इसकी प्रेरणा भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि वे कमल संदेश के इस विशेषांक 'नए भारत के प्रणेता' को जरूर पढ़ें और इससे प्रेरणा लें। यह विशेषांक पुस्तक और डिजिटल संस्करण, दोनों में उपलब्ध है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ मानवता की सेवा में जुटे रहें और देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दें, मेरा यही आग्रह है। मैं एक बार पुनः इस विशेषांक के लिए डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास एवं कमल संदेश की पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप लोगों ने काफी अच्छा और सराहनीय कार्य किया है।

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के कोषाध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया। 'कमल संदेश' के कार्यकारी संपादक डॉ. शिवशक्ति बक्सी ने विशेषांक के विषयवस्तु के बारे में बताया। न्यास के सचिव श्री नंदकिशोर गर्ग ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। ■

मोदी हैं, तो भरोसा है

जगत प्रकाश नड्डा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आज विश्वास और उम्मीद के प्रतीक हैं। उनके नेतृत्व में भारत आंतरिक मोर्चे, अंतरराष्ट्रीय मंच और आम जन के विषयों पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। जिन संकल्पों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जिन विषयों पर पार्टी अपने स्थापना काल से मुखर और सक्रिय रही और जिन कार्यों को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे मनीषियों ने आगे बढ़ाया, पार्टी के कोटि-कोटि कार्यकर्ताओं ने जिन अभियानों को देश के आम जन तक पहुंचाया और जो संकल्प भारत को विश्वगुरु बनाने तथा समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु लिए गए उन संकल्पों को देश मोदी जी के नेतृत्व में आज साकार होते देख रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इन छह सालों में देश के नागरिकों में गर्व और स्वाभिमान का संचार हुआ। अखिल विश्व में भारत के प्रति देखने और सोचने का नजरिया बदला। 'सवा सौ करोड़ देशवासी' शब्द हमारी क्षमता और गौरवबोध के संबल बने। नेतृत्व सक्षम हो तो वही परंपरागत तंत्र उच्च मनोबल के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने को आतुर रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी में आम नागरिक ने अपने जीवन की खुशहाली का समाधान देखा। उनके हर वाक्य को मंत्र माना। उनके हर अभियान में देश स्वतः स्फूर्त भागीदार बना। देश के प्रधानमंत्री के प्रति यह भाव व सम्मान होना देश और नागरिकों का सम्मान है, लोकतंत्र का सम्मान है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के रूप में प्रधान सेवक ने देश को विश्वास दिलाया कि यह जनतंत्र है जहां जनता ही जनार्दन है। सत्ता की कुर्सी सेवा के लिए है। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस अटूट विश्वास को जताती रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी उन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को स्पर्श करने का निरंतर प्रयास किया है।

प्रधानमंत्री जी का ही नेतृत्व है कि हर देशवासी उनके नेतृत्व में देश के प्रति अपने हर योगदान के लिए तत्पर रहता है। हमारे पड़ोसियों से सम्बन्ध जिन पूर्व की नीतियों और निर्णयों के कारण चले आ रहे थे। उन्हें प्रगाढ़ करने के प्रधानमंत्री जी के प्रयासों को देश जानता है। दो कदम आगे बढ़कर हाथ मिलाने और विश्वास करने का वातावरण भारत ने पूरे विश्व के सामने दिखाया। श्रद्धेय अटल जी के अमर वाक्य 'मित्र बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं' की दृष्टि से अपने पड़ोसियों से मित्रता को जीवंत करने के प्रयास ही नहीं किए, बल्कि पूरा विश्व गवाह है कि भारत किस तरह आत्मीयता और सम्मान से अपने संबंधों के प्रति आग्रही रहता है। पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीति पर भारत का पुराना रवैया और वर्तमान तेवर पाकिस्तान देख चुका है। आज चीन के साथ सीमा पर बनी स्थिति में देश मोदी जी के नेतृत्व में अटूट विश्वास रखते हुए भरोसा करता है, जिससे कि देश का सबसे प्रभावी और मजबूत स्टैंड आज चीन के सामने दिख रहा है जिसने बराबरी के साथ पड़ोसी को एहसास कराया कि नया भारत स्वाभिमान से जीने का आत्मबल लेकर चल रहा है, जहां नागरिक और राष्ट्रहित से समझौता नहीं होता है। यह मनोबल प्रधानमंत्री मोदीजी ने देश को दिया है।

'गरीबी' और 'आम जनता' अभी तक पोस्टरों और नारों में स्थायी भाव के साथ मौजूद थे। मोदी जी ने उनकी चिंताओं के

समाधान को धरातल पर उतारा। सरकार के वायदों पर टकटकी लगाकर प्रतीक्षा करने वाले देश के आम जन को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार उन्हीं की सेवा हेतु कृतसंकल्प है। आज देश के नागरिक सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। योजनाएं उनके जीवन के हर पहलू को स्पर्श कर रही हैं और पारदर्शी रूप में उनके पास चलकर आ रही हैं। समाज के हर वर्ग का अपनी सरकार के प्रति आदर भाव होना बताता है कि सरकार ने लोकतंत्र में लोक के सम्मान का भाव उत्पन्न किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कालखंड में गरीब को ध्यान में रखकर बनी योजना और नीति प्रत्यक्ष रूप से गरीब की सेवा कर रही है। उनके सम्मान, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार जैसे मूलभूत विषयों का मोदी सरकार द्वारा समाधान हो रहा है। शौचालय जैसे आवश्यक किंतु उपेक्षित विषय पर लाल किले की प्राचीर से चिंता जता कर मोदी जी ने पूर्व की परंपरा ही नहीं तोड़ी, बल्कि अहसास दिलाया कि राष्ट्र के संबोधन में केवल भारी भरकम विषयों और अलंकारों से कहने के बजाय धरातल की सच्चाई पर चर्चा होनी चाहिये और उसे साकार करने का संकल्प ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर लेना चाहिये।

जन-धन खाते, रोजगार, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत जैसे विषय बताते हैं कि सत्ता सुख भोगने या पीढ़ियों को उपकृत करने का साधन नहीं है। लीक से हटकर मोदी जी ने 'टू द पीपल, फ़ॉर द पीपल, बाय द पीपल' के विचार को सार्थक किया। आम जन को सरकार की उपयोगिता, सरकार के निर्णय और स्वयं नागरिक होने की जिम्मेदारी के बोध होने और राष्ट्रीय अभियानों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का वातावरण बनाया।

जन-धन खाते, रोजगार, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत जैसे विषय बताते हैं कि सत्ता सुख भोगने या पीढ़ियों को उपकृत करने का साधन नहीं है। लीक से हटकर मोदी जी ने 'टू द पीपल, फ़ॉर द पीपल, बाय द पीपल' के विचार को सार्थक किया। आमजन को सरकार की उपयोगिता, सरकार के निर्णय और स्वयं नागरिक होने की जिम्मेदारी के बोध होने और राष्ट्रीय अभियानों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का वातावरण बनाया।

पूर्व में दलों द्वारा सत्ता को स्थायी बनाए रखने के उपक्रम इस देश में चले। वोट बैंक के खेल के माइंडसेट से बाहर निकल कर देश के लिए सोचने का नजरिया प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्लूप्रिंट है, जिसमें गरीब, जरूरतमंद की चिंता प्राथमिक है। लोकतंत्र में विकास के अवसर क्षेत्र, वर्ग या व्यक्ति के आधार पर न होकर आवश्यकता के आधार पर होंगे। यह नजरिया आज सिस्टम में भी विकसित हुआ है। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाकर इसी विचार को पुष्ट किया गया है कि देश के सभी नागरिक और क्षेत्र समान हैं। सबका विकास समान अधिकारों के साथ होगा। हमारे पूज्य डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी विचार के लिए बलिदान दिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का सपना भी मोदी सरकार में ही मुमकिन हुआ। मुस्लिम बहनों के लिए तीन तलाक जैसा अपमानजनक विषय इसलिए समाप्त किया गया कि किसी समाज की आधी आबादी को किसी प्रथा से पीड़ित नहीं किया जा सकता। आजादी के बाद से ही सरकारों ने सरकारी सिस्टम को अपने निजी हितों को साधने और अपने सांचे में ढाल कर जिस तरह पिंजरे में बंद रखा था, आज वही तंत्र देश के आमजन के लिए जवाबदेह और दायित्वशील होकर विकास की नई इबारत लिख रहा है। यह सोच प्रधानमंत्री मोदीजी द्वारा सिस्टम को दिया गया नया नजरिया आज हमें उसके कामकाज में दिखाई दे रहा है।

प्रधानमंत्री जी ने सदैव अपने संबोधन में एक सौ पच्चीस करोड़ देशवासियों को देश की तकदीर बदलने वाला साधन और संसाधन माना। अभी तक जिसे भीड़ की संज्ञा और बढ़ती आबादी को सभी दिक्कतों की जड़ माना जाता था उसे नया नजरिया देकर प्रधानमंत्री जी ने उसे नए मायने दिए 'अगर हम उपभोक्ता हैं तो उत्पादक क्यों नहीं।' हमारी बाहरी देशों व तकनीकी पर निर्भरता बदलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया

जैसे अभियान देश की धमनियों में विकास रोजगार का संचार करने वाले साबित हुए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन में देश को हर बार नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार होता है देश उनके अभियान में स्वतः सम्मिलित हो जाता है। उनके प्रेरक अभियान देश को नया भारत बनाने के लिए है। पिछले 6 वर्षों में देश ने वे सभी बदलाव अनुभव किए हैं। जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती प्रधानमंत्री मोदीजी की सोच और दर्शन उन्हें देश के भरोसे का प्रतीक बनाती है।

वोकल फॉर लोकल का अभियान शुरू कर प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत को एक नई दिशा दी। मोदी हैं तो भरोसा है, यह भाव प्रधानमंत्री जी ने अचानक पैदा नहीं किया। 2014 की परिस्थितियां याद करें, तब देश केवल भ्रष्टाचार की चर्चाओं और अवसाद की स्थिति में घिरा था। प्रधानमंत्री मोदीजी ने इन परिस्थितियों से देश को उबारा ही नहीं बल्कि सकारात्मक मनोबल भी दिया।

एक अत्यंत निर्धन पृष्ठभूमि से आने वाले प्रधानमंत्री मोदीजी ने एक नागरिक के रूप में जिन अनुभवों का जीवन में साक्षात्कार किया, वह उनके चिंतन का स्थायी उत्प्रेरक है जिन्हें वे हर योजना, विचार और कार्यक्रम में प्रमुखता से स्थान देते हैं। आम आदमी उनकी इसी मौलिकता में अपनी निकटता देखता है। शौचालय एक महिला की निजी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, उस पर संवेदनशीलता की पराकाष्ठा तक जाकर सोचना और धरातल पर उसके समाधान को उतारने का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लाना दुरूह कार्य था, जो जन-आंदोलन बन गया। शौचालय न होने पर किसी महिला की विवशता का जिक्र उनके अनेक संबोधनों में मिलता है। ईंधन की व्यवस्था एक नारी की दिनचर्या का जरूरी और समय खपाने वाला हिस्सा था, जिसका समाधान उज्ज्वला योजना के रूप में एक महाभियान बन गया। प्रधानमंत्री मोदीजी द्वारा बेटियों की शिक्षा, स्वरोजगार, सुरक्षा और मातृत्व से लेकर वृद्धावस्था तक हर जगह सरकार की योजना का संबल देना बताता है कि पदों पर संवेदनशील व्यक्ति के बैठने पर किस तरह समाज को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है।

वैश्विक महामारी कोरोना पूरे विश्व को प्रभावित किया है। समाज और जीवन के हर क्षेत्र पर इसका असर पड़ा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना के कारण देशवासियों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। विश्वभर में भय और निराशा का वातावरण बना, किंतु भारत ने इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया। देश के 80 करोड़ लोगों को मार्च से नवंबर तक के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। 1.70 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 20 लाख करोड़ रुपये की निधि से आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई। गरीबों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना की शुरुआत की गई। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। वोकल फॉर लोकल का अभियान शुरू कर प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत को एक नई दिशा दी। मोदी हैं, तो भरोसा है, यह भाव प्रधानमंत्री जी ने अचानक पैदा नहीं किया। 2014 की परिस्थितियां याद करें, तब देश केवल भ्रष्टाचार की चर्चाओं और अवसाद की स्थिति में घिरा था। प्रधानमंत्री मोदीजी ने इन परिस्थितियों से देश को उबारा ही नहीं बल्कि सकारात्मक मनोबल भी दिया।

कोरोना काल से पहले देश में वेंटिलेटरों की अपेक्षित संख्या नहीं थी, हमारे स्वास्थ्य ढांचे का तंत्र वैश्विक महामारी से निपटने में सक्षम नहीं था। मास्क और सैनिटाइजर पर भी हमारी लगभग बाहरी निर्भरता थी। लॉकडाउन जैसे ऐतिहासिक निर्णय के समय संक्रमण को रोककर हमने अपने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत ही नहीं किया, बल्कि सैनिटाइजर और मास्क के उत्पादन से इस कोरोना काल में लघु उद्यम भी खड़ा किया और हमारी बाहरी निर्भरता भी समाप्त हुई। आज हम पीपीई, किट, फेस कवर और वेंटीलेटर्स निर्यात कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के छह वर्षों के कार्यकाल में देश की जनता को आजादी के बाद पहली बार इस बात की अनुभूति हुई है कि गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार कैसी होती है, देश को आगे ले जाने वाली सरकार कैसी होती है और देश के प्रति दुनिया के नजरिये में बदलाव लाने वाली सरकार कैसी होती है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

किसान कल्याण के नए मापदंड

अमित शाह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रही है। किसानों को लुभाने वाली घोषणाओं के बजाय प्रधानमंत्री का जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर रहा है। सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में कृषि सुधार से संबंधित तीन विधेयक सदन में लाए गए। पहला विधेयक देश के अन्नदाता को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति दिलाने के साथ-साथ उसे अपनी उपज को इच्छानुसार मूल्य पर बेचने की आजादी देगा। पहले हमारे किसानों का बाजार सिर्फ स्थानीय मंडी तक सीमित था, उनके खरीदार सीमित थे, बुनियादी ढांचे की कमी थी और मूल्यों में पारदर्शिता नहीं थी। इस कारण उन्हें अधिक परिवहन लागत, लंबी कतारों, नीलामी में देरी और स्थानीय माफिया की मार झेलनी पड़ती थी। अब उन्हें राष्ट्रीय बाजार में अवसर मिलने के साथ-साथ बिचौलियों से सही मायनों में मुक्ति मिलेगी। किसानों का 'एक देश-एक बाजार' का सपना भी पूरा होगा।

दूसरा विधेयक बोआई के समय ही बाजार से संपर्क प्रदान करता है, जिससे किसान के उत्पादन और मूल्य, दोनों से जुड़े जोखिम घटेंगे। इसके तहत किसान कृषि आधारित उद्योगों, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ अनुबंधित कृषि कर सकेंगे। अनुबंधित किसानों को ऋण की सुविधा, तकनीकी सहायता, बीज की उपलब्धता, फसल बीमा सुविधाएं आदि उपलब्ध कराई जाएंगी। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आने से स्टोरेज, परिवहन तथा एग्रो इंडस्ट्री लगने का रास्ता खुलेगा। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। वे कैश क्रॉप्स और एग्रो-इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार खेती कर अपनी आमदनी असीमित रूप से बढ़ा सकेंगे। यह अधिनियम किसानों के मालिकाना हक और खेती के अधिकार को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेगा। किसानों को किसी भी समय इस करार से बिना किसी पेनाल्टी के निकलने की आजादी होगी और जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना निषिद्ध होगा।

विपक्षी दल भूल जाते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जिन सिफारिशों को कांग्रेस सरकार ने 2006 में ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उन्हें मोदी सरकार ने पूरा किया है। मोदी सरकार एमएसपी में लगातार वृद्धि कर रही है, जिसकी एक बानगी गत दिवस भी देखने को मिली। अब 2014 की तुलना में गेहूं की एमएसपी 41 प्रतिशत, धान की 43, मसूर की 73, उड़द की 40, मूंग की 60, अरहर की 40, सरसों की 52, चने की 65 और मूंगफली की 32 प्रतिशत ज्यादा हो गई है।

कई राज्यों में बड़े किसान कॉरपोरेट के साथ मिलकर कैश क्रॉप का लाभ ले रहे थे। अब यह लाभ छोटे किसान भी ले सकेंगे, पर जिन विपक्षी दलों ने उन्हें हमेशा अंधकार और गरीबी में रखा, उन्हें यह बदलाव अच्छा नहीं लगा। वे सड़क से संसद तक इसका विरोध कर रहे हैं। इस दौरान राज्यसभा में उनका आचरण लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा को शर्मसार करने वाला था। ये वही लोग हैं जिनके शासन में किसानों की हालत बद से बदतर होती गई। वे बिचौलिये और साहूकारों द्वारा शोषित होते रहे और आर्थिक विकास का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला।

आज जब प्रधानमंत्री उन्हें वे अधिकार दे रहे हैं जो 70 वर्ष पूर्व ही मिलने चाहिए थे, तो इन नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा। वे यह कहकर भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म करने जा रही है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान इन विधेयकों में नहीं है। वह व्यवस्था यथावत रहेगी। वास्तव में अब किसानों के पास एमएसपी के अतिरिक्त भी उपज बेचने के कई विकल्प होंगे।

विपक्षी दल भूल जाते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जिन सिफारिशों को कांग्रेस सरकार ने 2006 में ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उन्हें मोदी सरकार ने पूरा किया है। मोदी सरकार एमएसपी में लगातार वृद्धि कर रही है, जिसकी एक बानगी गत दिवस भी देखने को मिली। अब 2014 की तुलना में गेहूं की एमएसपी 41 प्रतिशत, धान की 43, मसूर की 73, उड़द की 40, मूंग की 60, अरहर की 40, सरसों की 52, चने की 65 और मूंगफली की 32 प्रतिशत ज्यादा हो गई है। यही नहीं, 2014 की तुलना में गेहूं और धान की खरीद मात्रा में भी क्रमशः 73 और 114 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2009-14 तक कांग्रेस सरकार ने किसानों से मात्र 1.52 लाख मीट्रिक टन दालें खरीदीं, वहीं मोदी सरकार ने 2014-19 में 76.85 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद की। यह 4962 प्रतिशत का फर्क विपक्ष के ढोंग और मोदी जी के समर्पण को साफ दर्शाता है। स्पष्ट है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत दूसरे विपक्षी नेता न सिर्फ एमएसपी पर भ्रम फैला रहे हैं, बल्कि किसानों के विकास में रोड़ा भी बन रहे हैं।

शेष भाग पृष्ठ 21 पर...

नरेन्द्र मोदी: 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' के शिल्पकार

योगी आदित्यनाथ

नायको यस्य राष्ट्रस्य धृतिमान् मतिमान् भवेत्।
उन्नतिस्तस्य राष्ट्रस्य जायते नात्र संशयः।।

अर्थात् जिस राष्ट्र का नायक धैर्यशाली, बुद्धिमान होता है, उस राष्ट्र की सदैव उन्नति होती है, इसमें संशय नहीं है।

उक्त भावनाओं को समेकित रूप में देखना है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व इसमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। राष्ट्रभावों से ओतप्रोत, मां भारती के प्रति समर्पण की प्रतिमूर्ति, जनगण के मर्म को सम्मान देने वाले जननायक, मातृशक्ति और मातृभूमि के अगाध श्रद्धाभाव सम्पन्न प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन, उनके विचार और उनके संकल्प का ही परिणाम है कि जो राष्ट्र पिछले 70 वर्षों से बहुत लोकाचारों के तटबंधों के बीच ठहरा हुआ था, वह अब 'एक भारत—श्रेष्ठ भारत' बनकर सम्पूर्ण विश्व हर कदम पर उसकी तरफ देखने के लिए विवश है।

'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' के भाव को प्रधानमंत्री मोदीजी ने न केवल अपनाया बल्कि दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों का पवित्रता के साथ निर्वहन भी किया। 'बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ' के माध्यम से बेटियों के न केवल अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित किया बल्कि उन्हें सामाजिक और वित्तीय रूप से सक्षम एवं स्वावलम्बी बनाने का सत्कार्य भी किया। 2014 के पहले मातृ शक्ति के सम्मान की सिर्फ बातें होती थीं। स्वच्छ भारत अभियान ने उनके उस मान की रक्षा ही नहीं की बल्कि नारी गरिमा की रक्षा के साथ ही बालिकाओं के स्कूल ड्रॉप रेट को रोककर उन्हें शिक्षित और कुशल बनाया ताकि वे अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं कर सकें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने मातृशक्ति को न केवल कार्बनजनित बीमारियों से बचाया बल्कि उन्हें सामाजिक गौरव की अनुभूति भी करायी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना, फ्री सिलाई योजना, बालिका अनुदान योजना, विद्या लक्ष्मी शिक्षा ऋण योजना और प्रधानमंत्री श्री मातृवंदना योजना जैसी बहुत सी योजनाएं हैं जो मातृशक्ति को कुशल, प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाकर नारी शक्ति को राष्ट्रशक्ति का पूरक बनाने में समर्थ हैं।

आजादी के पहले से ही हमारे राष्ट्रनायक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की बात करते आए हैं। लेकिन आजादी के 70 वर्षों में इसे कोई भी जमीन पर नहीं उतार पाया किन्तु

जो राष्ट्र पिछले 70 वर्षों से बहुत लोकाचारों के तटबंधों के बीच ठहरा हुआ था, वह अब 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' बनकर सम्पूर्ण विश्व हर कदम पर उसकी तरफ देखने के लिए विवश है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसे जमीन पर उतारा भी और उसकी अनुभूति भी करायी। जनधन जैसी योजनाओं ने जब इस अंतिम व्यक्ति को राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था से सीधे जुड़ने का अवसर दिया तो पहली बार उसे यह अनुभूति हुई कि राष्ट्र के बैंक उनके लिए हैं और वह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की एक इकाई है। इससे भी महान कार्य है भारत के जन के भाव को समझना और उसे राष्ट्रभाव से जोड़ना। जनोत्थान को राष्ट्रोत्थान की थाती बनाना। सभी को एक प्रकार से और एक जैसा सोचने के लिए प्रेरित करना। अंत्योदय को राष्ट्रोदय के सांचे में ढालना। यह सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे। सच में, महाकुंभ के समय गंगा के तट पर जब वे उन स्वच्छताकर्मियों, जिनसे जनसामान्य भी दूरी बनाए रखता है, के पांव पखार रहे थे तो सही अर्थों में वे अंत्योदय से राष्ट्रोदय तक की भारत की यात्रा को सम्पन्न कर रहे थे।

प्रधानमंत्री मोदीजी आज के युग में राष्ट्रनीति के प्रतिबिम्ब हैं। उनकी दूरदृष्टि राष्ट्र को जीवंत और समर्थ बनाती है। कोरोना की महामारी में आज हम जिन वजहों से स्वयं को बचाने में सफल हो रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री ने आज से 5-6 वर्ष पहले ही अपनाने के लिए प्रेरित किया था। कोरोना महामारी में सबसे कारगर मंत्र स्वच्छता का है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने 02 अक्टूबर 2014 में ही इसे अभियान के रूप में शुरू कर दिया था। कोरोना काल में शिक्षा से लेकर व्यवस्था तक और चिकित्सा से लेकर अध्यात्म तक का सबसे सशक्त माध्यम वर्चुअल प्लेटफार्म साबित हुआ। जबकि प्रधानमंत्री जी ने 6 साल पहले ही डिजिटल इंडिया की सशक्त नींव रख दी थी। प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रत्येक जन के मन को छुआ और उसकी आवश्यकताओं को ही नहीं बल्कि आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए योजनाएं शुरू कीं। आज जब वे अपने जीवन के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं उन्हें भारत को 70 से अधिक ऐसी योजनाएं देने का श्रेय जाता है जो भारत के जन गण के साथ-साथ भारत राष्ट्र के उन्नयन का इतिहास लिख रही हैं।

2014 से पहले दो विशिष्ट विचारधाराओं ने एकेडमीशिया पर कब्जा कर रखा था। इसके चलते भारत अपने मूल चरित्र से लम्बे समय तक वंचित रहा। इस कारण से वैश्विक मंचों पर भारत की साख घटी और वैश्विक वैचारिकी में भारत के लिए सॉफ्ट स्टेट यानी कायर राज्य जैसे शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर्मठता, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव, अपने विचारों और कूटनीतिक क्षमता से भारत राष्ट्र और उसके 135 करोड़ लोगों के मान और सम्मान को पुनर्प्रतिष्ठित किया। जो अमेरिका कभी उन्हें वीजा देने से ऐतराज कर रहा था उसी अमेरिका ने टाइम्स स्क्वायर पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत को देखा और भारत की जीवंत शक्ति को भी। उसी अमेरिका

ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में भारत को एक विजेता के रूप में देखा, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए देखा गया। प्रधानमंत्री ने पड़ोसी प्रथम नीति के जरिए भारत के पड़ोसी राज्यों को वह सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे और वर्षों से उसकी अपेक्षा करते आए थे। हमारी एक्ट ईस्ट और पीवोट टू वेस्ट ने पूरब और पश्चिम के बीच एक महान सेतु का काम किया। इसी का परिणाम है कि जिस ओआईसी ने भारत को पाकिस्तान के दबाव में आमंत्रण तक नहीं दिया था उसी ओआईसी ने पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत के लिए पलक पांवड़े बिछाए।

कई अरब देशों द्वारा प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया जो यह बताता है कि प्रधानमंत्री सार्वभौम एवं सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व हैं। आज के दिन दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत से जुड़ना नहीं चाहता, जो भारत के साथ मिलकर चलना नहीं चाहता और जो भारत के साथ नयी विश्वव्यवस्था में नवनिर्माणों को सम्पन्न नहीं करना चाहता। इसका श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री को जाता है, यह उन्हीं के व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण ही संभव हुआ है।

अयोध्या और कश्मीर दो ऐसे विषय हैं जो पूरे भारतीय जनमानस के मन को प्रायः कचोटते थे। अयोध्या सही अर्थों में लगभग 500 वर्षों से गुलामी जैसा अभिशाप झेल रही थी। भगवान श्रीराम के जन्मस्थान को मुक्त कराने के लिए हिन्दू समाज प्राणों की आहुतियां देता चला आ रहा था। 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री ने श्रीराम मंदिर की नींव रखी तो ऐसा लगा कि ऋषियों, यतियों और योगियों द्वारा किया जाने वाला राष्ट्रयज्ञ सम्पन्न हुआ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 दशकों से भारतीय मानस को आहत करता था क्योंकि इसके रहते 'एक भारत—श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना अधूरी थी। प्रधानमंत्री ने अपने दृढ़संकल्प और अपनी प्रबल राजनीतिक इच्छा से इसे हटाकर राष्ट्रनायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक निशान, एक विधान, एक प्रधान' के संकल्प को साकार किया।

वैश्विक महामारी कोराना की विभीषिका के सम्मुख जब अनेक विकसित राष्ट्र पूरी तरह से पस्त थे उस दुस्साध्य कालखण्ड में प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदर्शिता, कुशल नियोजन तथा बड़े और कड़े निर्णय लेने की क्षमता के कारण ही आज 'जान और जहान' दोनों सुरक्षित हैं।

आजादी के बाद के लम्बे कालखण्ड में भारत कुछ लोकाचारों से मुक्त नहीं हो पाया था, जिसमें सबसे बड़ा पक्ष था अर्थव्यवस्था के साथ नये एवं अन्वेषी आयामों का न जुड़ पाना। प्रधानमंत्री ने जनधन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन की नींव रखी, डिजिटल इण्डिया के द्वारा अर्थव्यवस्था को अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदला और साथ ही भारत को टैक्नोलॉजिकल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सांचे में ढाला। जीएसटी के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत हुई और 'वन टैक्स वन नेशन' के साथ ही आर्थिक कड़ियां मजबूत हुईं और भारत एक प्रतिस्पर्धी, टैक्नोलॉजिकल और स्किल्ड राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ा।

यह मेरा सौभाग्य है कि शुचिता, संस्कार, संवेदना और सेवा की समृद्ध परम्परा के जाज्वल्यमान प्रतीक पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमें जनसेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि 'एक भारत—श्रेष्ठ भारत' के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सान्निध्य हमें आजीवन ऐसे ही प्राप्त होता रहे। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय का संकल्प सुफलित हो रहा है, यही आत्मनिर्भर भारत का वास्तविक मंत्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिवस की कोटि-कोटि बधाई। आपके सुदीर्घ यशस्वी और सुखद जीवन की कामना के साथ—

ध्रुवं ते राजा वरूणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः।
ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम।। (ऋग्वेद 10वां मण्डल, सूक्त 5) ■

(लेखक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

पृष्ठ 19 का शेष...

जहां कई विपक्षी पार्टियों ने वर्षों तक किसानों के नाम पर केवल राजनीति की, वहीं मोदी सरकार ने शास्त्री जी के 'जय जवान-जय किसान' नारे को आगे ले जाते हुए दर्जनों ऐसे काम किए हैं, जिनसे किसान तेजी से खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कृषि बजट में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 16.38 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए, माइक्रो इरिगेशन में 39.4 फीसद वृद्धि हुई, कृषि यंत्रीकरण का बजट 1248 गुना किया गया, कृषि ऋण 57 फीसद अधिक दिया गया और कृषि ऋण में दी जाने वाली छूट में निवेश 150 फीसद बढ़ा।

इसी कारण मोदी सरकार के छह वर्षों के कार्यकाल में खाद्यान्न उत्पादन 7.29, बागवानी का 12.4 और दलहन का 20.65 फीसद बढ़ा है। इसके अतिरिक्त फसल बीमा योजना से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। इससे बीमित किसानों की संख्या 6.66 करोड़ से बढ़कर 13.26 करोड़ हो गई है। पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम किसान पेंशन योजना के माध्यम से किसानों को सीधी सहायता देने का भी काम किया गया है। अब तक 10.21 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 94 हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि सीधे उनके खातों में भेजी गई है। पेंशन योजना से भी अब तक 19.9 लाख किसान जुड़ चुके हैं। मोदी सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये की कृषि मूलभूत संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण की एक नई केंद्रीय योजना भी शुरू की है।

मोदी सरकार ने आरसेप से बाहर आकर भी किसानों को चीन के नकारात्मक प्रभाव से बचाया। सरदार पटेल का कहना था, 'इस धरती पर अगर किसी को सीना तानकर चलने का हक है तो वह धन-धान्य पैदा करने वाले किसान को है।' मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मोदी सरकार ने किसानों को यह अधिकार देने का काम किया है। किसानों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे इन कदमों का सुपरिणाम शीघ्र ही देश के समक्ष आएगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए हो रहे प्रयासों में हमारे अन्नदाता किसानों की बराबर की भूमिका होगी। ■

(लेखक केंद्रीय गृह मंत्री हैं)

नरेन्द्र मोदी: विकसित भारत का वैश्विक चेहरा

सर्बानंद सोनोवाल

भारत को विश्वगुरु के आसन पर प्रतिष्ठित करने के लक्ष्य से महान जननेता, विशाल व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मूल्यबोध एवं भारतीय दर्शन पर आधारित उठाए गए कदमों से वैश्विक स्तर पर हमारे देश की छवि मजबूत हुई है। इस महान व्यक्ति का जीवन और कर्म आज विश्ववासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। राजनीति, समाज नीति, अर्थव्यस्था, विज्ञान, तकनीक समेत सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की लहर बहाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरेक भारतीय के आत्मविश्वास को सुदृढ़ किया है।

चुनौतियों के समक्ष सिर नहीं झुकाने वाले इस विश्व समादरित नेता का जीवन जिस तरह से आलोकित हुआ है, वह हरेक व्यक्ति के लिए अत्यंत प्रेरक है। एक चाय दुकान से विश्व के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। चुनौतियों के विरुद्ध साहस के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ने की प्रगाढ़ मानसिकता के अधिकारी हैं मोदीजी। आर्थिक रूप से कमजोर एक परिवार में जन्म लेकर पिता के उपार्जनस्थली एकमात्र चाय दुकान में हाथ बंटाते हुए मोदी जी ने जिस तरह अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, यह उनकी दृढ़ निश्चय का परिचायक है। कठोर जीवन संग्राम में लगे रहने के बावजूद भारतमाता की सेवा की अदम्य इच्छा के कारण वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुए हैं। कठोर परिश्रम के आदर्श और पिता के प्रति अनुराग समाज के लिए एक विरल दृष्टिकोण है।

2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश को विश्व में शक्तिशाली बनाने के लिए 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की नीति के आधार सभी जाति-जनजाति, भाषा-भाषी, धर्मावलंबी लोगों को लेकर उन्होंने जो यात्रा आरंभ की थी, उसका फलदायी परिणाम आज हरेक भारतवासी देख रहा है। इस महान नेता के भविष्य में झांकने की क्षमता के कारण अप्रवासी भारतीय भी आज स्वयं को भारतीय कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। प्रत्येक विदेश दौरे में मिले अपार आदर और स्नेह पर्वतसम व्यक्तित्व के धनी इस प्रधानमंत्री की विश्वव्यापी लोकप्रियता को प्रमाणित करता है।

प्रधानमंत्री जी पांच हजार वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता-संस्कृति से समग्र देशवासी को आगे लेकर बढ़े और विश्वमंच को हमारे देश की शक्ति और सामर्थ्य से परिचित कराने के लिए किए गए उनके प्रयास के फलस्वरूप विश्व की 750 करोड़ आबादी भारत की तरफ आकर्षित हुई। भारतीय संस्कृति और मूल्यबोध ने आज विश्व को नई प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2015 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की औपचारिक घोषणा करके विश्व नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्रदान की। मोदी जी के मजबूत पदक्षेप के कारण ही आज विश्ववासी विश्व शांति, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए योगाभ्यास की जरूरत को समझ पाए हैं।

21वीं सदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। नई-नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश की नई पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'डिजिटल इंडिया अभियान' का नारा दिया था, तब अधिकतर लोग उनके इस पदक्षेप की गहराई समझ नहीं पाए थे। विज्ञानसम्मत नजरिये से संचार साधन, प्रशासन में पूरी तरह पारदर्शिता और सभी कामकाज डिजिटल माध्यम से पूरा करके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की उनकी पहल से आज देश तेजी से आगे बढ़ने में सफल हुआ है। आज आगामी पीढ़ी आगे बढ़कर 'डिजिटल इंडिया' के स्वप्न को वास्तविक रूप देने के लिए खुद आगे बढ़ रही है। कोविड-19 जैसे महासंकट के समय देशवासियों ने डिजिटल के उपयोग की गंभीरता और महत्व को समझा। शिक्षा से लेकर सरकारी-गैरसरकारी कार्यालयों में कामकाज आज डिजिटल माध्यम से करना संभव हो पाया है।

उसी तरह देश की सभी जाति-जनजाति की स्वयं की भाषा-संस्कृति को पुनर्जीवित कर स्वाभिमान के साथ जीवित रह सके, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति' से जो राह दिखाई गई है, उसे आज देशवासी अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। विश्व मंच पर आधुनिक चिंतनधारा को आगे बढ़ाने के साथ-साथ भारतीय परंपरा व मूल्यबोध की नींव पर जीवन गढ़ने के लिए यह शिक्षा नीति नई आशा और उत्साह ले आई है। नई शिक्षा नीति के वास्तविक रूप से लागू होने से भारतवर्ष विश्व का बौद्धिक ज्ञान केंद्र बन उठेगा।

प्रधानमंत्री जी वैश्विक स्तर पर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लक्ष्य से आरंभ से ही कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मोदीजी की अगाध आस्था है। प्रधानमंत्री के रूप में संसद में पहली बार प्रवेश करने के समय संसद भवन की सीढ़ी पर मत्था टेक कर लोकतंत्र के प्रति अपनी गहरी आस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री जी ने यह दर्शाया है कि संसदीय लोकतंत्र हमारे जीवन का प्रवाह और विकास का पावन क्षेत्र है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने स्वयं को एक सेवक बताया है। देश सेवा ही उनके जीवन का

मूलमंत्र है, पिछले छह वर्षों से देशवासी स्वयं अपनी आंखों से इसे देख रहे हैं।

भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी के उठाए गए कदमों से आज देशवासियों में आत्मविश्वास बढ़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, भारत-चीन सीमा पर भारतीय सेना की मजबूत स्थिति–प्रधानमंत्री का देश के प्रति गंभीर दायित्व का प्रमाण है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर उन्होंने भारतवासियों में 'एक राष्ट्र, एक संविधान' के आदर्श की अवधारणा कायम की है। महात्मा गांधी के रामराज्य के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भारतीय मूल्यों पर आधारित जो-जो कदम उठाए हैं, वे सब हमारे लिए एक महत आदर्श हैं। 500 वर्ष पुराने राम मंदिर भूमि विवाद का कानून के अनुसार निपटारा तथा राम मंदिर भूमि पूजन कर माननीय प्रधानमंत्री ने देशवासियों की दीर्घकालिक आकांक्षाओं को पूरा किया है।

देश के अन्य प्रदेशों के साथ ही असम तथा पूर्वोत्तर को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी आरंभ से ही पूरी दृढ़ता के साथ विभिन्न कदम उठा रहे हैं। इसके पहले के किसी भी प्रधानमंत्री ने असम तथा पूर्वोत्तर की प्राकृतिक संपदाओं और संभावनाओं को लेकर इस तरह का काम नहीं किया था। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध होने के बावजूद पहले की सरकारों की उपेक्षा के कारण इस क्षेत्र के लोगों का मनोबल तेजी से गिरने लगा था। फलस्वरूप पूर्वोत्तर के लोग देश की विकास प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। इसके विपरीत आज माननीय प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीति के कारण इस अंचल के आम लोगों का मनोबल बढ़ा है।

इस युगद्रष्टा ने पूर्वोत्तर को 'अष्टलक्ष्मी' और 'देश के विकास का इंजन' मानते हुए तेजी के साथ विकास योजनाओं को लागू करने लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इस अंचल के लिए केंद्रीय योजनाएं समय पर और सही ढंग से लागू हो सकें, इसके लिए उन्होंने हरेक केंद्रीय मंत्री को हर पखवाड़े एक बार इस अंचल का दौरा करने का निर्देश दिया है। वहीं देश के इतिहास में एक मिसाल कायम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं 30 से अधिक बार इस अंचल का दौरा किया है। यह दर्शाता है कि पूर्वोत्तर के लिए उनके हृदय में कितना गहरा लगाव है। प्रधानमंत्री जी के 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के जरिए असम तथा पूर्वोत्तर के साथ दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के उपायों के फलस्वरूप यातायात, संचार, व्यवसाय-वाणिज्य, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, खेल, सूचना-तकनीक, कृषि इत्यादि हर क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं।

भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी के उठाए गए कदमों से आज देशवासियों में आत्मविश्वास बढ़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, भारत-चीन सीमा पर भारतीय सेना की मजबूत स्थिति–प्रधानमंत्री का देश के प्रति गंभीर दायित्व का प्रमाण है।

प्रधानमंत्री जी ने असमिया जाति के मान-सम्मान को आज देश और दुनिया में विशिष्ट पहचान दिलाई है। निजी जीवन के साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय-अतंरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में असमिया गामोछा पहनकर उन्होंने असमिया बुनकरों के स्वाभिमान को विश्व भर में उज्ज्वलित किया है। बुनकरों के हथकरघे में बुने सपनों को मान देकर उन्होंने समग्र जाति के स्वाभिमान को बढ़ाया है। सुधाकंठ डॉ. भूपेन हजारिका को देश का सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' प्रदान कर असमिया संस्कृति को और अधिक उज्ज्वल करने के साथ ही हमारे क्षेत्रीय स्वाभिमान को नए रूप में संजीवनी दी है। असम की हरेक जाति-जनगोष्ठी के प्रति उनकी सद्भावना अतुलनीय है। बीटीआर समझौते के जरिए राज्य में शांति स्थापना के प्रयासों के फलस्वरूप आज राज्य में विकास प्रक्रिया को विशेष गति मिली है।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों के समक्ष कर्म-संस्कृति की नई मिसाल पेश की है। एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के सपने को साकार करने की दिशा में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। दूसरों को उपदेश देने के बजाय स्वयं एक आदर्श स्थापित करते हुए मोदी जी ने आज देशवासियों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया है। रोजाना 20 घंटे काम में लगे रहकर उन्होंने एक आदर्श दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है।

देश के प्रत्येक व्यक्ति के समान विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं को समर्पित किया है। विशेष रूप से समर्थ व्यक्ति को दिव्यांग की आख्या देकर उन्हें सामाजिक मान-मर्यादा और स्वाभिमान से जीवन-यापन का अवसर उपलब्ध कराया है। महिला, शिशु, किसान, श्रमिक, बेरोजगार सभी के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें जमीनी स्तर तक ले जाने में सफल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण मंद पड़ी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की और अब उसे लागू भी किया जा रहा है। 'आत्मनिर्भर' भारत बनाने के प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से देशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। देशवासियों के हित में किसी सरकार द्वारा वृहद आर्थिक पैकेज घोषित करने का उदाहरण भारत के इतिहास में नहीं मिलता।

गौरवमयी संस्कृति और परंपरा से समृद्ध भारतवर्ष गढ़ने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों ने आज देशवासियों में आत्मानुभति का संचार किया है। हरेक नागरिक राष्ट्र निर्माण का हिस्सेदार बनने को उत्सुक है। देश की प्रगति की गति को तेज करने के प्रधानमंत्री के प्रयासों से भारतवर्ष का विश्व का एक प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र बनना निश्चित है। इस बात को यथार्थ अनुभवों के साथ हम सभी समझ चुके हैं। ■

(लेखक असम के मुख्यमंत्री हैं)

नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व मानवता के कल्याण के लिए

प्रभात झा

विश्व के सबसे अधिक जनसमर्थन वाले प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि गुजरात के लाल, श्री नरेन्द्र मोदी के दर्शन और कर्तव्यपरायणता महात्मा गांधी के निकट है। गांधीजी द्वारा प्रतिपादित मानवता, समानता और समावेशी विकास के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत के अब तक के सबसे जनप्रिय प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया है। जन सेवा और राष्ट्र धर्म का उन्होंने अनुपालन कर जो आदर्श स्थापित किया है, एक सुनहरे भारत का निर्माण तो करेगा ही विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। नव भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को लेकर एक श्रेष्ठ और समर्थ भारत के निर्माण को संकल्पित व समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 70 वर्ष के हो गए।

7 अक्टूबर 2001 को श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 12 वर्षों में गुजरात में हुए अभूतपूर्व एवं समग्र विकास के आधार पर तथा यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और नीतिगत पंगुता से त्रस्त पूरे देश ने श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के एकमात्र विकल्प के रूप में स्वीकार्यता दिलाई। 26 मई, 2014 को उनके नेतृत्व में पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिला और वे देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। 'सबका साथ, सबका विकास' और 'एक भारत श्रेष्ठ' के मूलमंत्र से उन्होंने देश का जो अभूतपूर्व सर्वांगीण विकास किया, इससे उन्होंने जन-जन के हृदय में अपनी जगह बनाई। जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से 2019 के आम चुनाव में उन्हें ऐतिहासिक समर्थन मिला और 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। ऊर्जावान, समर्पित एवं दृढ़ निश्चयी श्री नरेन्द्र मोदी प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाओं और आशाओं के द्योतक हैं। नव भारत के निर्माण की नींव रखने वाले श्री नरेन्द्र मोदी करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का चेहरा हैं। 26 मई 2014 से, जबसे उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, देश को विकास उस शिखर पर ले जाने के लिए अग्रसर हैं, जहां हर देशवासी अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के अंतिम पायदान पर खड़े एक-एक व्यक्ति के पूर्ण विकास को 24x7 समर्पित हैं।

एक प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी की अंतर्दृष्टि, संवेदना, कर्मठता, राष्ट्रदर्शन व सामाजिक सरोकार स्वतंत्र भारत के अब तक के इतिहास में अद्वितीय है। उनकी विचारशैली और उनकी कर्तव्यपरायणता अतुलनीय है। वे केवल जनप्रिय नहीं है, वे जन-जन के प्रिय हैं। उनका चिंतन राष्ट्र चिंतन है बन गया। मई 2014 से लेकर आज सितंबर 2020 के छह साल साढ़े तीन महीने के अपने रिकॉर्ड प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उन्होंने जन सेवा और राष्ट्र धर्म के जो आदर्श स्थापित किये हैं, भारतीय राष्ट्र के बेहतर भविष्य के लिए अनुकरणीय है। 14 अप्रैल को उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्र को संबोधित करते हुए यजुर्वेद के एक श्लोक का उल्लेख किया था - 'वयं राष्ट्रे जागृत्य', अर्थात हम सभी अपने राष्ट्र को शाश्वत और जागृत रखेंगे। आज यह पूरे राष्ट्र का,जन-जीवन का संकल्प बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिक और राष्ट्र के प्रति सेवा धर्म का जो कर्तव्यपथ तैयार किया है, सम्पूर्ण भारत का उनको साथ है। लेकिन यह राह कम चुनौतयों से भरा नहीं रहा है। व्यक्तिगत जीवन हो या राजनीतिक जीवन, पूर्व के सभी प्रधानमंत्रियों की तुलना में इनका जीवन अधिक कठिनाइयों भरा रहा है। लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी हर परीक्षा में शत-प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होते रहे हैं। आज कोरोना महामारी में अपेक्षाकृत कम चिकित्सा सुविधा होने के बावजूद श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में कहीं बेहतर ढंग से इस महामारी से लड़ रहा है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जब पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी, तब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुरुआती फंड के तहत 2.25 लाख रुपये का योगदान दिया। पीएम केयर्स फंड में जमा राशि से भारत आज प्रभावी रूप से विश्व में सबसे बेहतर तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। पीएम केयर्स फंड का उपयोग कोरोना से और भविष्य में इस प्रकार की गंभीर चुनौतियों का शीघ्रता और तत्परता से निपटने के लिए चिकित्सीय ढांचागत सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। भारत का यह सशक्त होता सामर्थ्य, श्री नरेन्द्र मोदी की जन और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण तथा उनके नेतृत्व में जन आस्था का परिणाम है।

प्रधानमंत्री के रूप में विश्व में त्याग और मानवता के अनुपम उदाहरण हैं श्री नरेन्द्र मोदी। मानवता और राष्ट्र की सेवा में अब तक 103 करोड़ रुपये अपने व्यक्तिगत फंड से दान कर चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान मिले सभी उपहारों की नीलामी कर मिले 89.96 करोड़ रुपये को कन्या केलवनी फंड, 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने से पहले अपने निजी बचत के 21 लाख रुपये गुजरात सरकार के कर्मचारियों की बेटियों की पढ़ाई के लिए, 2015 में मिले उपहारों की नीलामी से जुटाए गए 8.35 करोड़ रुपये नमामि गंगे मिशन को, 2019 में कुंभ मेले में निजी बचत से 21 लाख रुपये स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाए गए फंड को, 2019 में ही साउथ कोरिया में सियोल पीस प्राइज़ में मिली 1.3 करोड़ की राशि को स्वच्छ गंगा मिशन को, हाल ही में अपने कार्यकाल के दौरान उनको मिली स्मृति चिन्हों की नीलामी में 3.40 करोड़ रुपये एकत्र किए गए राशि को भी

नमामि गंगे मिशन को उन्होंने दिए। वहीं पीएम केयर्स फंड के लिए 2.25 लाख रुपये दिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा' की भावना से समाज और सेवा कर रहे हैं।

5 अगस्त को भारतीय जन आस्था के केंद्र और राष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी अयोध्या में भगवान् श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन के अवसर पर पधारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा 'राम काज किन्हें बिनु, मोहि कहां विश्राम।' उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का संदेश, हमारी हजारों सालों की परंपरा का संदेश, कैसे पूरे विश्व तक निरंतर पहुंचे, कैसे हमारे ज्ञान, हमारी जीवन-दृष्टि से विश्व परिचित हो, ये हम सबकी, हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि श्रीराम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला ये भव्य राममंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा और वहां निर्मित होने वाला राममंदिर अनंतकाल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्वतंत्र भारत के सबसे परिवर्तनकारी नेतृत्व हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन देखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उदय सत्ताधारी दल के रूप में एक नई राजनीतिक सोच तथा शैली के रूप में हुआ, जिसने कांग्रेस की छह दशकों की श्रेष्ठता को अप्रासंगिक बना दिया। श्री नरेन्द्र मोदी के परिवर्तनकारी एवं प्रभावी नेतृत्व में आधुनिक, डिजिटल, भ्रष्टाचार-मुक्त, जवाबदेह और विश्वसनीय सरकार का आविर्भाव हुआ है तथा जनता को भी अभूतपूर्व रूप से भागीदार बना दिया है। जहां अप्रासंगिक पुरातन प्रणालियों और नियमों को समाप्त कर दिया गया है, वहीं सैकड़ों योजनाओं और अभियानों के माध्यम से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। 'सबके साथ' और 'सबके विश्वास' से 'सबका विकास' हो रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी न केवल राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बल्कि एक कवि हृदय साहित्यकार भी हैं। अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद उन्होंने दर्जनभर पुस्तकें लिखी हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजराती भाषा में 67 कविताएं लिखी थीं। उनकी इन कविताओं के माध्यम से उनके दर्शन,उनके विचार और उनकी दृष्टि का सहजता के साथ अंदाजा लगाया जा सकता है। उनका हिन्दी में एक कविता संग्रह है 'साक्षी भाव' जिसमें जगत जननी मां से संवाद रूप में व्यक्त उनके मनोभावों का संकलन है, जिसमें उनकी अंतर्दृष्टि, संवेदना, कर्मठता, राष्ट्र दर्शन व सामाजिक सरोकार के स्पष्ट दर्शन होते हैं। उनकी श्रेष्ठतम रचनाओं में शामिल है 'पुष्पांजलि ज्योतिपुंज' जिसमें उन्होंने लिखा है कि संसार में उन्हीं मनुष्यों का जन्म धन्य है, जो परोपकार और सेवा के लिए अपने जीवन का कुछ भाग अथवा संपूर्ण जीवन समर्पित कर पाते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी समाज के प्रति दायित्व का बोध कराया है, तथा राष्ट्र सर्वोपरि को जीवन का मूलमंत्र माननेवाले ऐसे ही तपस्वी मनीषियों का पुण्य-स्मरण भी किया है। 'सामाजिक समरसता' नामक पुस्तक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समाज और सामाजिक समरसता के प्रति भावनाओं के प्रबल प्रवाह को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। इस पुस्तक में उनकी समाज के प्रति अद्वितीय दृष्टि और दृष्टिकोण की स्पष्टता है। जहां वे 'एग्जाम वॉरियर्स' नामक अपने पुस्तक में अपने बचपन के कई उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को परीक्षा के तनाव से निकलने की युक्ति बताते हैं, वहीं 'कनवीनिएंट एक्शन' में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और समाज को सचेत करते हैं और साथ ही इससे निपटने के लिए वैश्विक अभियान में शामिल होने की प्रेरणा भी देते हैं। अद्भुत हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की के नेतृत्व में राजनीति और सत्ता से परे जो मानव दृष्टि है, वैश्विक दृष्टि है, उनकी विश्व नेतृत्व की क्षमता का दर्शन कराता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राजनीतिक दर्शन का मूलमंत्र अंत्योदय है। प्रत्येक निर्णय के केंद्र में वंचित, गरीब, मजदूर, किसान हैं। जन-जन की चिंता है। 'अन्नदाता सुखी भवः' की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, नीति आधारित प्रशासन की संकल्पना है। शीघ्र निर्णय का मूल सिद्धांत है। प्रत्येक परिवार को पक्का घर मिले। चौबीस घंटे बिजली मिले। स्वच्छ पीने का पानी मिले। गांव-गांव सड़क, इंटरनेट हो। सबका पोषण, सबको उत्तम स्वास्थ्य मिले। सबको शिक्षा मिले। सबको रोजगार मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के योग्य और निर्णायक नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से किबिथू तक 'एक राष्ट्र, एक कर', 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का सपना साकार हो रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, स्वच्छ इंडिया, टीम इंडिया के सामूहिक प्रयत्नों से न्यू इंडिया का निर्माण हो रहा है। जन सेवा के साथ-साथ 'राष्ट्ररक्षासमं पुण्यं, राष्ट्ररक्षासमं व्रतम्, राष्ट्ररक्षासमं यज्ञो, दृष्टो नैव च नैव च' का संकल्प है। लेकिन उनके लिए मानवता और विश्व बंधुत्व का स्थान सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व मानवता के कल्याण के लिए है, भारतीय राष्ट्र के कल्याण के लिए है, विश्व के कल्याण के लिए है। श्री नरेन्द्र मोदी आप और अधिक यशस्वी बनें, दीर्घाऊ हों, शताऊ हों! ■

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का सपना साकार हो रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, स्वच्छ इंडिया, टीम इंडिया के सामूहिक प्रयत्नों से न्यू इंडिया का निर्माण हो रहा है। जन सेवा के साथ-साथ 'राष्ट्ररक्षासमं पुण्यं, राष्ट्ररक्षासमं व्रतम्, राष्ट्ररक्षासमं यज्ञो, दृष्टो नैव च नैव च' का संकल्प है।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद हैं।)

बिहार को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर प्रशस्त करना है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 12 सितंबर 2020 को बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय से 'आत्मनिर्भर बिहार' अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल, बिहार के उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार के प्रभारी श्री भूपेन्द्र यादव, केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रविशंकर प्रसाद, केन्द्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय सहित प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेता, जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। अपने उद्बोधन के पश्चात् उन्होंने 'आत्मनिर्भर बिहार' डिजिटल रथ को भाजपा का झंडा दिखाकर रवाना किया।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया गया है, इस संकल्प की अगुवाई बिहार आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होते हुए करेगा। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बिहार के फल, चाहे वो लीची हो, जर्दालू आम हो, आंवला हो, मखाना हो या फिर मधुबनी पेंटिंग्स हो, ऐसे अनेक उत्पाद बिहार के जिले-जिले में हैं जिनसे वोकल फॉर लोकल की तर्ज़ पर बिहार को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए भाजपा 'आत्मनिर्भर बिहार अभियान' की शुरुआत करने जा रही है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पास नेता भी है, नीति भी है और कार्यक्रम भी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा, जद (यू) और एलजीपी का एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और विजयी होगी। ■

'संपूर्णता के साथ किसान का विकास होना चाहिए'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 12 सितंबर 2020 को बिहार के मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा में मखाना एवं मत्स्य उत्पादकों और पद्मश्री किसान चाची के गांव (सरैया, मुजफ्फरपुर) में लीची एवं महिला किसानों को संबोधित किया और किसानों का वंदन करते हुए उन्हें आगे बढ़ने का मंत्र दिया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल, बिहार के उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी श्री भूपेन्द्र यादव उपस्थित थे। दरभंगा में भाजपा सांसद श्री गोपालजी ठाकुर, विधायक श्री संजय सरावगी एवं जिला भाजपा अध्यक्ष श्री जीवछ सहनी मंच पर मौजूद रहे तो पद्मश्री किसान चाची के (सरैया, मुजफ्फरपुर) में बिहार सरकार में मंत्री श्री सुरेश शर्मा, मुजफ्फरपुर के सांसद श्री अजय निषाद, विधायक श्री अशोक सिंह और किसान चाची पद्मश्री राजकुमारी देवी जी उपस्थित रहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पद्मश्री किसान चाची के गांव जाकर उनसे मुलाक़ात की और उनके अनुभवों से अवगत हुए।

श्री नड्डा ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आने के बाद देश में आशा, बदलाव और परिवर्तन की किरण देखी है।

प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। पहले कांग्रेस-राजद एंड कंपनी द्वारा गरीबों, दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति की जाती थी और उनका वोट हड़प कर उन्हें भुला दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सच्चे अर्थों में दलितों, गरीबों, शोषितों और वंचितों की चिंता की है और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कई योजनाओं का सूत्रपात किया है। ■

प्रधानमंत्री ने बिहार में 14,258 करोड़ रुपये की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 सितंबर को वीडियो कांफ्रेंस के ज़रिये बिहार में 14,258 करोड़ रुपये की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने बिहार के सभी 45,945 गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन राजमार्ग परियोजनाओं से बिहार में सड़क संपर्क बेहतर होगा। राजमार्ग परियोजनाओं में 3 बड़े ब्रिज और राजमार्गों को चार लेन तथा 6 लेन में अपग्रेड किया जाना शामिल है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब सभी नदियों पर पुल होंगे और सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का काम होगा।

श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि सरकार देश के हर एक गांव को आत्मनिर्भर भारत के अभियान से जोड़ने जा रही है और इसका शुभारंभ बिहार से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से 1000 दिनों में जोड़ा जाएगा जिससे तेज इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसमें 45,945 गांव बिहार के हैं। कुछ वर्षों पहले कल्पना से भी परे था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहरों की तुलना में अधिक होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल लेनदेन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में से है। अगस्त 2020 के दौरान यूपीआई के माध्यम से तीन लाख करोड़ रुपये के मूल्य का लेनदेन किया गया। इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि देश के हर एक गांव को बेहतर गुणवत्ता वाले और तेज स्पीड के इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों के प्रयास के चलते डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों और तीन लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर यानी सामान्य सेवा केन्द्रों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है।

तेज गति के इंटरनेट की सुविधा के फायदे का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे छात्रों को अध्ययन के लिए मौजूद बेहतर डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी। इसके साथ-साथ टेलीमेडिसिन, बीजों से जुड़ी जानकारियों तक किसानों की पहुंच होगी, किसानों को राष्ट्रव्यापी बाजारों और नई तकनीकों के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ मौसम के बारे में ताजा जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि किसान आसानी से अपने उत्पाद न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरी सुविधाओं को देश के हर एक ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना है।

श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी विकास से संबंधित योजना और इसके विकास के बारे में सबसे पहले तब प्रयास किए गए जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। जिन्होंने राजनीति के ऊपर बुनियादी ढांचा विकास को प्राथमिकता दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब प्रयास यह है कि देश में बहुस्तरीय परिवहन नेटवर्क विकसित हो और सभी आपस में जुड़े हों। बुनियादी ढांचा विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर इस समय जितना काम हो रहा है और जिस गति से इस काम को निपटाया जा रहा है वह अतुलनीय है। आज राजमार्गों के निर्माण की गति 2014 से पहले के मुकाबले दोगुनी हो गई है। 2014 से पहले की तुलना में राजमार्ग निर्माण पर खर्च 5 गुना बढ़ा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने आगामी 4 से 5 वर्षों के भीतर बुनियादी ढांचागत विकास पर 110 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। इसमें 19 लाख करोड़ रुपए राजमार्गों के विकास के लिए समर्पित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़क और संपर्क को बेहतर करने के लिए बुनियादी ढांचा को विस्तार दिए जाने की इन परियोजनाओं का लाभ बिहार को भी मिल रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि बिहार में आवागमन में सबसे बड़ी बाधा बड़ी नदियों के चलते थी, इसीलिए बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा में पुलों के निर्माण को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया था। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत गंगा नदी पर 17 पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से अधिकांश पूर्ण होने के चरण में है। इसी तरह से गंडक और कोसी नदियों पर भी पुलों का निर्माण किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पटना रिंग रोड और पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर तथा विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुलों के निर्माण से पटना और भागलपुर के बीच संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा। ■

आज देश वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मजयंती के अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों से बात की। इस अवसर पर पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े तो सभी प्रदेश कार्यालय और पार्टी पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, पार्टी के सांसद, विधायक भी इस कार्यक्रम से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्रीमती स्मृति ईरानी, श्री प्रकाश जावडेकर, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं केन्द्रीय कार्यालय मंत्री श्री अरुण सिंह सहित कई केन्द्रीय मंत्री, वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज उन सभी दिवंगत कार्यकर्ताओं को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके सेवा भाव के लिए, उनके अथक परिश्रम के लिए मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनकी प्रेरणा युक्त सेवा-साधना की परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी रहेगी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आधुनिक भारत का महान मनीषी बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र और समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो योगदान दिया है, वह पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति समाज नीति और

राजनीति, इन चारों को भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात मुखरता से कही थी और लिखी भी थी। 21वीं सदी के भारत को विश्व पटल पर नई ऊंचाई देने और 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के

एक राष्ट्र और समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो योगदान दिया है, वह पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है।

जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज जो कुछ भी हो रहा है, उसमें पंडित दीनदयाल जी जैसे महान व्यक्तित्वों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से ही देश के ईमानदार करदाताओं के हितों को सुरक्षा देने वाला फेसलेस अपील का प्रावधान भारत की टैक्स व्यवस्था से जुड़ने वाला है। ईमानदार करदाताओं को परेशानी न हो, इसके लिए फेसलेस टैक्स सिस्टम कुछ महीने पहले ही टैक्स रिजीम का हिस्सा हो चुका है। आज जब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक-एक देशवासी अथक परिश्रम कर रहा है, तब गरीबों, दलितों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, मज़दूरों को उनका हक देने का बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है।

श्री मोदी ने कहा कि बदलते हुए समय में बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता ने इस दौर में जिस तरह की Flexibility और adoptability दिखाई है, वह भी प्रशंसनीय है। कोरोना काल में भी हमने ये कर दिखाया है। समाज की सेवा में सक्रियता दिखाने के साथ-साथ दल और कार्यकर्ता के रूप में हमें एक और बात का विशेष ध्यान रखना है। हमारी बातें, हमारे विचार और हमारा आचरण 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप ही होने चाहिए। हमारे आदर्श, हमारी परंपरा, हमारी प्रेरणा जितनी प्राचीन है, उतनी ही नवीन भी होनी चाहिए। हम भले ही दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हों लेकिन हमारी पहुंच भारत के छोटे से छोटे गांव तक, छोटी से छोटी गली तक होनी ही चाहिए। अगर कोरोना के इस कालखंड की ही बात करें, तो दो गज़ की दूरी, मास्क, हाथ की साफ-सफाई, इन सभी के लिए जागरूकता फैलाना, निरंतर जरूरी है। हमें खुद भी इन नियमों का सख्ती से पालन करना है और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना है। आज देश वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ बातों से ही संभव नहीं होगा। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। ■

दीनदयालजी के विचारों पर कार्य करते हुए हम जन-सामान्य के सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 25 सितंबर 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मजयंती के अवसर पर पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से पंडित दीनदयाल जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्रीमती स्मृति ईरानी, श्री प्रकाश जावडेकर, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं केन्द्रीय कार्यालय मंत्री श्री अरुण सिंह सहित कई केन्द्रीय मंत्री, वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के माध्यम से देश को एक वैकल्पिक विचारधारा दी जो भारत की मिट्टी की सुगंध से ओत-प्रोत रही। उन्हीं के दिए संस्कार से पार्टी की सेवा-भाव की संस्कृति विकसित हुई। पंडित दीनदयाल जी के 'अंत्योदय' के सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के न केवल मंत्र को शासन पद्धति की नींव बनाया, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसे पहुंचाकर इसे चरितार्थ भी किया।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हर योजना में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े ही हैं और हमें इस बात का गर्व है। प्रधानमंत्री

जी के नेतृत्व में एक ओर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया, गांवों और कस्बों को खुले में शौच से मुक्त किया गया तो वहीं दूसरी ओर 8 करोड़ से अधिक गरीब

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हर योजना में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े ही हैं और हमें इस बात का गर्व है।

महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा 'आयुष्मान भारत' लागू की गई तो करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवच दिया गया। आयुष्मान भारत योजना से केवल दो वर्ष में अब तक लगभग 1.30 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए डेढ़ करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया गया और यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश के हर गरीब के पास अपनी पक्की छत होनी चाहिए। जल्द ही यह सपना भी साकार होगा। मुद्रा योजना के माध्यम से देश के लगभग 25 करोड़ लोगों को सहायता पहुंची और लगभग ढाई करोड़ से अधिक घरों में सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाई गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर वर्ष देश के प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 90 हजार करोड़ रुपये किसानों के एकाउंट में ट्रांसफर किये जा चुके हैं। इसके साथ ही, संसद के मानसून सत्र में पारित कृषि सुधार के विधेयकों के बल पर किसानों को सही मायनों में आजादी मिली है। अब किसान अपने फसल कहीं भी और अपनी कीमत पर बेच सकते हैं। कृषि सुधार के माध्यम से किसानों के सशक्तिकरण के लिए मैं पार्टी एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करता हूं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब भी पार्टी ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है, एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हम सबका, पार्टी का मार्गदर्शन किया है। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से न केवल हमारे कार्यकर्ता प्रेरित होंगे, बल्कि उनके मार्गदर्शन में आगे चलते हुए देश और समाज के उत्थान के लिए और प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके बताये रास्ते पर पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हो देश और समाज की सेवा में अविरत कार्य करते रहेंगे। ■

राज्य कोविड की टेस्टिंग, ट्रेसिंग पर प्रभावी उपाय करते रहेंगे: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितंबर को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य टेस्टिंग, ट्रेसिंग पर प्रभावी उपाय करते रहेंगे और कहा कि घरों पर आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 मरीजों के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी का तंत्र विकसित किया जाए।

साथ ही, श्री मोदी ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए कहा कि इन 2 वर्षों में 1.25 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिली है। उन्होंने चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों द्वारा गरीबों को दी जा रही अनवरत सेवाओं के लिए प्रशंसा की।

राज्यों की समीक्षा

प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार और लोगों के बीच बेहतर समन्वय के चलते स्थितियों में सुधार हुआ है। हर एक जीवन को बचाने के महत्व पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में जिन 20 जिलों में सबसे ज्यादा कोविड-19 मामले हैं उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आरटी-पीसीआर परीक्षण राज्य में वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रभावित जिलों वर्तमान क्षमता से 5 गुना बढ़ाने का सुझाव दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक ने ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के लिए एक वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित की है जिससे राज्य को व्यापक रूप में फायदा पहुंचा है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में जिन 9 जिलों में मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, वहां तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आरटी-पीसीआर परीक्षण वर्तमान स्तर से 3 गुना बढ़ाने, प्रभावी निगरानी और संपर्कों का पता लगाने तथा मास्क लगाने और साफ-सफाई को लेकर आ रहे व्यवहार में बदलाव के संबंध में भी ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है।

दिल्ली का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रभाव के चलते स्थितियां नियंत्रण में आई थीं। उन्होंने सुझाव दिया कि आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। यह टेस्ट उन सभी लोगों का भी किया जाना आवश्यक है जो एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाए जा रहे हैं।

श्री मोदी ने पंजाब की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि शुरुआती समय में पंजाब कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में सफल था, लेकिन अब स्थितियां बिगड़ी हैं। कोविड के चलते ज्यादातर मौतों की वजह मरीजों का देर से अस्पताल पहुंचना है। उन्होंने कहा कि राज्य को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य पॉजिटिव दर और मृत्यु दर को नीचे लाने में सफल होगा।

प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु का जिक्र किया और कहा कि राज्य बड़े पैमाने पर परीक्षण और मामलों का पता लगाने की अपनी रणनीति के चलते हर दिन आने वाले मामलों की संख्या को स्थिर करने और उसे कम करने में सफल हुआ है। उन्होंने राज्य के 7 जिलों में मृत्यु दर कम किए जाने पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेलीमेडिसिन के लिए राज्य ने ई-संजीवनी एप्लीकेशन का अच्छा इस्तेमाल किया है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का अनुभव निश्चित रूप से अन्य राज्यों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहां बीते दिनों में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर वापस लौटे थे। इन स्थितियों के बीच भी राज्य परीक्षण बढ़ाकर स्थिति को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सफल रहा है।

श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य संपर्कों का पता लगाने पर युद्ध स्तर पर काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में 16 जिले ऐसे हैं जहां हर दिन 100 से ज्यादा मामले आ रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग और मास्क तथा 2 गज दूरी के नियम का पालन करने के बारे में लोगों को निरंतर जागरूक करने पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

वायरस से निपटने के लिए और अधिक धन

प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि मामलों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि देश में प्रतिदिन 10 लाख से अधिक कोविड-19 के परीक्षण किए जा रहे हैं। साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वाइरस का मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। मामलों का पता लगाने यानी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए तंत्र बेहतर करने तथा और अच्छी प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

श्री मोदी ने घोषणा की कि कोविड-19 संबंधी स्वस्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग 35% से बढ़ाकर 50% किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्यों को वायरस से मुकाबले में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने राज्यों से वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर एक दो दिनों का लॉकडाउन लगाने और उसके प्रभावों का आकलन करने का सुझाव दिया, बशर्ते राज्य में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। श्री मोदी ने कहा कि हमें न वायरस से लगातार लड़ाई जारी रखनी है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती से आगे बढ़ना है।

टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, सर्विलांस और संदेश

प्रधानमंत्री ने प्रभावी परीक्षण, संपर्कों का पता लगाने, मरीजों का इलाज करने, निगरानी और स्पष्ट संदेश संप्रेषित करने की व्यवस्था को और बेहतर करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि एसिंप्टोमेटिक प्रकृति के चलते परीक्षण को लेकर संदेह न बढ़े, इसके लिए प्रभावी संदेश संप्रेषण की व्यवस्था को प्रभावी करने की आवश्यकता है। उन्होंने दैनिक आधार पर मास्क का उपयोग करने की आदत विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्री मोदी ने राज्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में हाल में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में बाधा सामने आई है, जबकि मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस समय की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। श्री मोदी ने संपूर्ण राज्य में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने को कहा।

बैठक के दौरान केंदीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि देश ने वायरस का मुकाबला करने की दिशा में लॉकडाउन के समय अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया। उन्होंने कहा कि राज्यों और जिलों को वायरस से मुकाबले के लिए तैयार होने की आवश्यकता है इसके संबंध में बैठक के दौरान मिली प्रतिक्रियाओं की मदद से दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव ने विस्तृत प्रस्तुति दी जिसमें उन्होंने बताया कि देश के कुल कोविड-19 मामलों में 62% मामले 7 राज्यों में है और कोविड-19 के चलते हुई कुल मौतों में 77% मौतें इन्हीं 7 राज्यों में हैं। इस प्रस्तुति में 7 राज्यों के उन जिलों को रेखांकित किया गया जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले हैं, परीक्षण ज्यादा किए गए हैं, मृत्यु दर ज्यादा है और परीक्षण में पॉजिटिव आने वाले मामलों की दर भी ज्यादा है।

मुख्यमंत्रियों के वक्तव्य

इस बैठक में मुख्यमंत्रियों ने इस आपदा के समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने अपने-अपने राज्य द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की दिशा में आने वाली चुनौतियों, तैयारियों और अब तक विकसित किए गए स्वास्थ्य ढांचे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने, मृत्यु दर कम करने, पोस्ट कोविड केयर क्लीनिक शुरू करने, परीक्षण बढ़ाने सहित अब तक उठाए गए सभी कदमों के बारे में भी जानकारी दी। ■

किसानों को उपज बेचने का विकल्प देकर उन्हें सशक्त बनाया गया है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने 20 सितंबर, 2020 को राज्य सभा से उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक धन्यवाद दिया और सभी किसानों को बधाई दी। ज्ञात हो कि ये विधेयक लोक सभा से दो दिन पहले ही पारित हो गए थे।

श्री नड्डा ने संसद के गलियारे में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 70 सालों में किसानों के सशक्तिकरण के लिए जो कदम नहीं उठाये जा सके, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विगत छः वर्षों में साकार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कृषि की बेहतरी और किसानों के उत्थान के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। आज राज्य सभा से पारित हुए कृषि से जुड़े दोनों विधेयक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 किसानों को अपने फसल के भंडारण, और बिक्री की आजादी देंगे और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्त करेंगे।

आजादी के 70 सालों में किसानों के सशक्तिकरण के लिए जो कदम नहीं उठाये जा सके, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विगत छः वर्षों में साकार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कृषि की बेहतरी और किसानों के उत्थान के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पहले किसान अपने उत्पादों को मंडी में ही बेचने पर विवश थे, उनके पास कोई सहूलियत नहीं थी। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर ने आज ये दोनों विधेयक राज्य सभा के पटल पर रखा और पार्टी एवं सहयोगी सांसदों के समर्थन से ये विधेयक सदन से पारित हुए। कृषि विधेयकों के पारित होने पर मैं समग्र भारत के किसानों को बधाई देता हूं एवं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विशेष धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इन प्रगतिशील विधेयकों के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए ऐसी व्यवस्था की कि किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिले। इन विधेयकों के पारित होने से किसानों को पुराने सभी बंधनों से आजादी मिली है और अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसानों को उपज बेचने का विकल्प देकर उन्हें सशक्त बनाया गया है। बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का भी लाभ किसान ले सकेंगे। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान किसान के घर पर ही उपलब्ध होगा।

राज्य सभा में विपक्ष के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार की कड़ी भर्त्सना करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा जिस तरह से संसद में अमर्यादित और अलोकतांत्रिक व्यवहार किया गया, वह प्रजातंत्र पर कुठाराघात है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। कांग्रेस एवं उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों ने सदन के पटल किसान हितैषी वाले इन विधेयकों का विरोध करके यह स्पष्ट कर दिया है कि ये पार्टियां किसान विरोधी हैं और ये किसानों का सशक्तिकरण होते नहीं देख सकते। आज किसानों को दोनों विधेयकों के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो आजादी मिली है, उसे रोकने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों द्वारा सदन में किया गया। आज जब किसानों के लिए ऐतिहासिक आजादी का दिन था, तब विपक्ष को इन विधेयकों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए था पर बिल का समर्थन करने के बजाय उन्होंने इसे रोकने का हर संभव प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भी ख़त्म करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा और भर्त्सना करती है।

कांग्रेस एंड कंपनी पर हमले की धार को और तेज करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि राज्य सभा में कांग्रेस और कुछ पार्टियों द्वारा आज जो कुछ भी हुआ, वह यह दिखाता है कि उन्हें प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। जो सभ्य आचरण एक सांसद का होना चाहिए, उसे आज सदन में तार-तार करने की कोशिश की गई। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है। इसके साथ ही, हेल्थ प्रोटोकॉल की भी अवहेलना की गई। इसकी जितनी भी निंदा की जाय, कम है।

श्री नड्डा ने कहा कि कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने व किसानों को सशक्त कर उनकी आमदनी बढ़ाने व किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले कृषि सुधार विधेयकों के देश के दोनों सदनों में पारित होने पर एक बार पुनः मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को साधुवाद देता हूं एवं सभी अन्नदाता किसानों को इसकी बधाई देता हूं। ■

कृषि सुधार विधेयकों में कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे किसानों का कोई भी नुकसान होने वाला है: नरेन्द्र सिंह तोमर

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 24 सितंबर, 2020 को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया और संसद द्वारा पारित कृषि सुधार के विधेयकों कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विस्तार से चर्चा करते हुए कांग्रेस की किसानों को गुमराह करने वाली राजनीति पर जमकर प्रहार किया।

कृषि सुधार का विरोध करने वाली कांग्रेस की तुलना 'हाथी के दांत' से करते हुए श्री तोमर ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी कि उसे इन विधेयकों के विरोध से पहले अपने घोषणापत्र से मुकरने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संसद में पारित कृषि सुधार विधेयकों में कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे किसानों का कोई भी नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा, ''जो कृषि सुधार के विधेयक हैं, ये किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। इनके माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता मिलने वाली है। ये किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने में मददगार होंगे।'' उन्होंने आगे कहा कि इन विधेयकों के माध्यम से किसान नई तकनीक से जुड़ेगा। इसके कारण किसान अपनी उपज का सही मूल्य बुआई से पहले भी प्राप्त कर सकेगा।

संसद में पारित कृषि सुधार विधेयकों में कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे किसानों का कोई भी नुकसान होने वाला है। जो कृषि सुधार के विधेयक हैं, ये किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। इनके माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता मिलने वाली है।

श्री तोमर ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व बौना हो गया है। कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं उनकी पूछ खत्म हो गई है। कांग्रेस में जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है उनकी कोई हैसियत देश में बची नहीं है। उनकी अपनी पार्टी में ही कोई नहीं सुनता है। कांग्रेस के कुछ नेता देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह APMC एक्ट को बदल देगी, किसान के ट्रेड पर कोई टैक्स नहीं होगा और अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा देंगे। यही बातें संसद से पारित विधेयकों में है। वास्तव में कांग्रेस हाथी के दांत की तरह है - खाने के और और दिखाने के और। कांग्रेस का कोई भी नेता चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का, उसे पहले ये बोलना चाहिए कि हमने जो चुनावी वादे किए थे उसे अब हम पलट रहे हैं। कांग्रेस अगर इन विधेयकों का विरोध कर रही है तो उसे पहले अपने घोषणा पत्र से मुकरने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है, उसे अब तत्काल समाप्त कर देना चाहिए।

श्री तोमर ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में किसान को अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता था और मंडी में बैठे कुछ चुनिंदा आढ़तिया बोली लगाकर किसान की उपज की कीमत तय करते थे, कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होने पर किसान को मजबूर होकर मंडी में ही माल बेचना पड़ता था। लेकिन, अब किसान मंडी के बाहर भी अपनी उपज बेच सकेगा और वह भी अपनी मर्जी के भाव पर। इन कृषि सुधार विधेयकों से किसान को उनकी फसल के दाम की गारंटी फसल बुआई के पूर्व ही मिल जाएगी। साथ ही, किसान कॉन्ट्रेक्ट खेती के लिए जो करार करेंगे, उसमें सिर्फ कृषि उत्पाद की खरीद फरोख्त होगी, जमीन से खरीदार का कोई लेना-देना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को यह भी सहूलियत दी गई है कि अगर वह कांट्रेक्ट तोड़ते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि खरीदार कॉन्ट्रेक्ट नहीं तोड़ सकेगा। कृषि उपज मंडियां पहले की तरह काम करती रहेंगी क्योंकि वे राज्य सरकार के अधीन होती हैं। पहले कृषि उपज मंडियों में बेचने पर किसान को टैक्स भी देना पड़ता था, लेकिन बाहर फसल बेचने पर उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात ये है कि अधिकतम तीन दिनों के भीतर क्रेता को किसान को भुगतान करना होगा। किसी विवाद की स्थिति में दोनों मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और इस मामले का 30 दिन में हल किया जाएगा। हम जानते हैं कि 86 प्रतिशत छोटा किसान है। छोटे रकबे वाले किसानों के पास निवेश नहीं पहुंचता। कई बार उसे MSP का फायदा भी नहीं मिलता। इसलिए बिल के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट के जरिए किसान को फसल के मूल्य की गारंटी मिलती है। ■

केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 3,82,581 शेल कंपनियों को बंद किया

केंद्र सरकार ने मुखौटा (शेल) कंपनियों की पहचान करने और इन्हें बंद करने (कंपनी रजिस्टर से नाम हटाना) के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। लगातार दो साल या इससे अधिक समय से वित्तीय विवरणों (एफएस) के दाखिल नहीं करने के आधार पर कंपनियों की पहचान की गई और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 तथा कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के तहत कानून की उचित प्रक्रिया के पालन के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान 3,82,581 कंपनियों को बंद कर दिया गया है। यह बात 20 सितंबर को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कही।

कंपनी अधिनियम के तहत 'शेल कंपनी' को पारिभाषित नहीं किया गया है। यह आम तौर पर उस कंपनी को इंगित करता है, जो सक्रिय कारोबार का संचालन नहीं करती है या कंपनी के पास महत्वपूर्ण परिसंपत्ति नहीं है और इन कंपनियों का इस्तेमाल कुछ मामलों में अवैध उद्देश्य के लिए किया जाता है जैसे कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, अस्पष्ट स्वामित्व, बेनामी संपत्ति आदि। 'शेल कंपनी' के मामले की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेष कार्य बल ने कुछ सिफारिशें की हैं, जिनमें शामिल है- शेल कंपनियों की पहचान के लिए अलर्ट के रूप में कुछ रेड फ्लैग संकेतकों का उपयोग करना। ■

बिहार विधान सभा चुनाव के तारीखों की घोषणा

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीन चरणों वाले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राज्य की 243 सीटों पर तीन चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में 28 अक्टूबर को राज्य की 16 जिलों की 71 सीटों पर, दूसरे चरण में 3 नवंबर को राज्य की 17 जिलों की 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को राज्य 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग कराया जाएगा। राज्य में मतों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी।

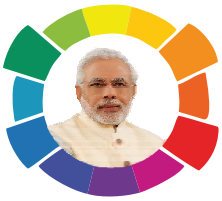

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

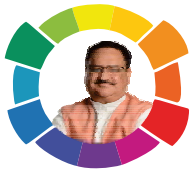

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के रेहड़ी–पटरी विक्रेताओं के साथ स्वनिधि संवाद करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत '21वीं सदी में स्कूली शिक्षा' पर एक सम्मेलन को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईटी, गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित तीन प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

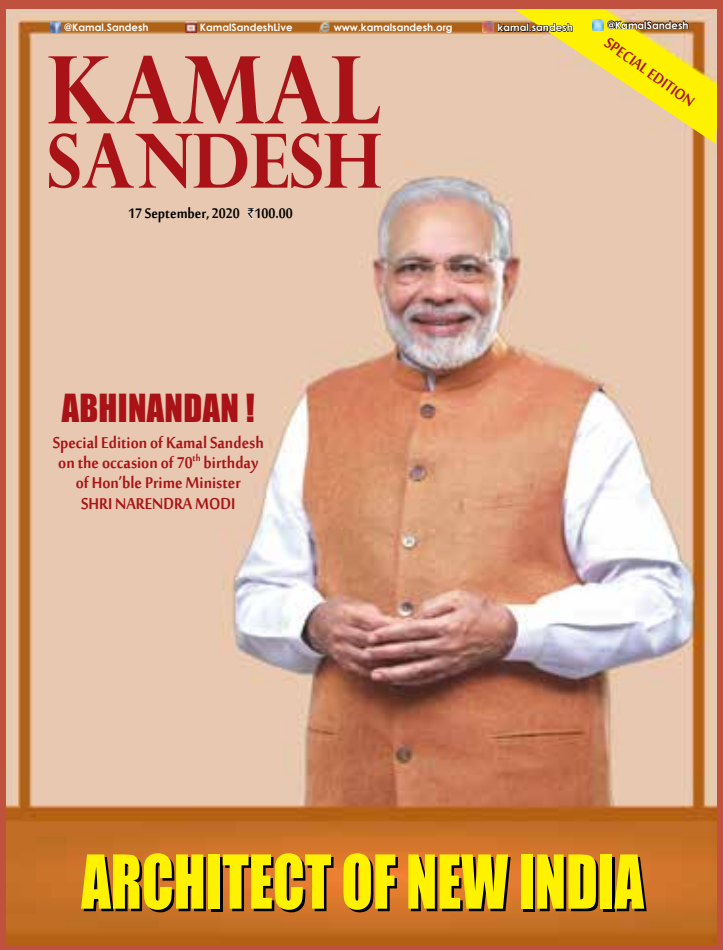

ARCHITECT OF NEW INDIA

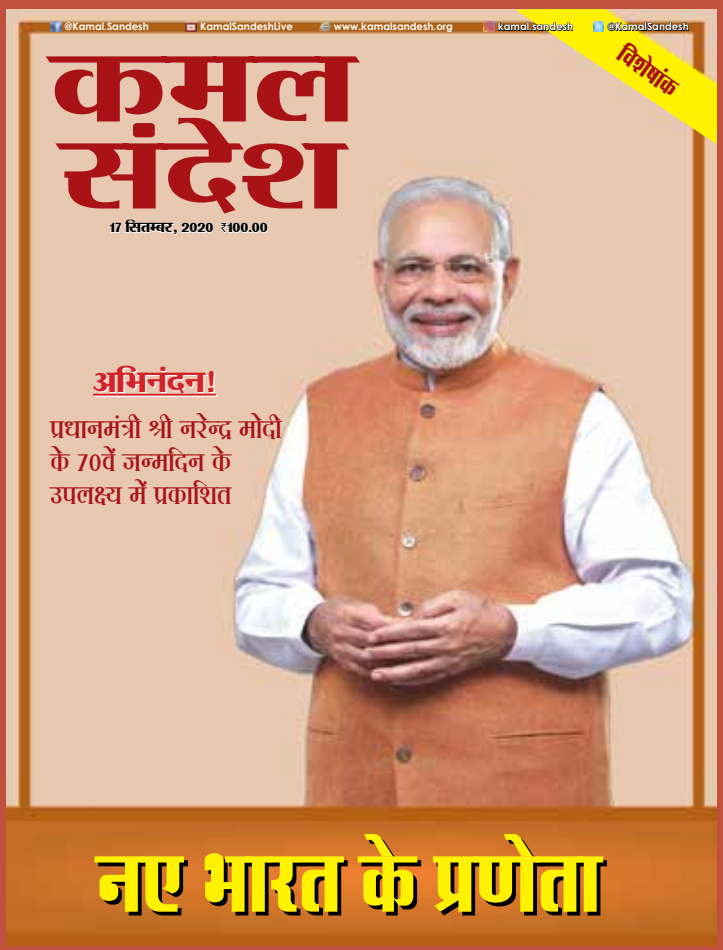

नए भारत के प्रणेता

'कमल संदेश' विशेषांक को पढ़ने व डाउनलोड करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें:
www.kamalsandesh.org